www.adbhutsamachar.com

अद्भुत समाचार

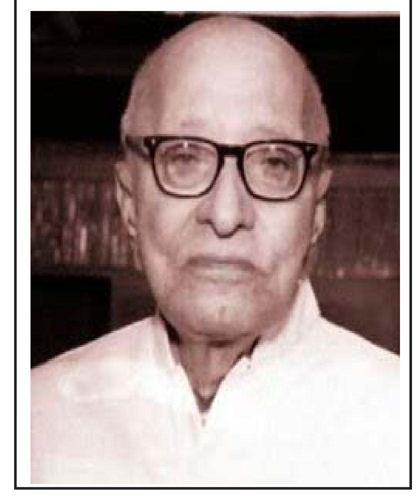

वर्ष – 15 | अंक–46 | RNI-No.: UPHIN/2011/43806 | लखनऊ,बुधवार 14 जनवरी, 2026 | प्रातः कालीन संस्करण | (हिन्दी दैनिक) | पृष्ठ–4 | मूल्य 1 रुपया

'प्रगति' नए भारत की कार्यसंस्कृति का सशक्त माडल, उत्तर प्रदेश बना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रो–एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि नए भारत की नई कार्यसंस्कृति का प्रभावी और सशक्त उदाहरण है। मंगलवार को आयोजित विशेष प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रगति' उस प्रशासनिक मॉडल का प्रतिबिंब है, जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रखी थी और 2014 के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब इरादा (इंटेंट), तकनीक और जवाबदेही एक साथ आती हैं तो परिणाम स्वतः सुनिश्चित हो जाते हैं। डिजिटल गवर्नेंस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूती देते हुए प्रगति एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है, जहां अंतर–मंत्रालयीय और अंतर–विभागीय समन्वय के माध्यम से जटिल समस्याओं का समयबद्ध समाधान संभव हुआ है।उन्होंने बताया कि प्रगति मॉडल की अवधारणा वर्ष 2003 में गुजरात में 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेज बाई एप्लिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) के रूप में प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य नागरिक शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। यही मॉडल आगे चलकर 'प्रगति' के राष्ट्रीय स्वरूप में विकसित हुआ, जिसने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, सामाजिक योजनाओं और सिस्टम रिफॉर्म के क्षेत्र में 'टीम इंडिया' अप्रोच को मजबूती दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति केवल एक रिव्यू मैकेनिज्म नहीं, बल्कि एक गवर्नेंस रिफॉर्म है। इसने शासन को फाइल–केंद्रित संस्कृति से निकालकर फील्ड–आधारित परिणामों की दिशा में अग्रसर किया है। इसके चलते निर्णय प्रक्रिया तेज हुई है, समय और लागत की बर्बादी रुकी है और केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित हुई है।राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति के प्रभाव का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके माध्यम से ₹86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को गति मिली है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 377 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है। वहीं, 3162 में से 2958 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है, जो शासन की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति मॉडल राज्य के लिए एक गेम–चेंजर सिद्ध हुआ है। आज उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। एक्सप्रेस–वे नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, सर्वाधिक शहरों में मेट्रो संचालन, एयर कनेक्टिविटी, देश की पहली रैपिड रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और रोपवे जैसी परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ी हैं, जिनके पीछे निरंतर समीक्षा और समस्या–समाधान का प्रभावी मंच प्रगति रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास ₹10.48 लाख करोड़ की लागत वाली 330 परियोजनाओं का देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है। इनमें परिवहन, ऊर्जा, शहरी विकास, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रमुख प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें से ₹2.37 लाख करोड़ की लागत की 128 परियोजनाएं (39 प्रतिशत) पूर्ण होकर कमीशन हो चुकी हैं जबकि ₹8.11 लाख करोड़ की 202 परियोजनाएं निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रगति पर हैं।उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए सभी अड़चनों का समाधान किया जा रहा है और इसमें प्रगति एक मजबूत आधार बनकर सामने आया है।

आदित्य साहू का झारखण्ड बीजेपी अध्यक्ष बनना तय
प्रेसीडेन्ट पद के एकमात्र उम्मीदवार, 14 को औपचारिक घोषणा

झारखंड भाजपा के संगठनात्मक चुनाव में आदित्य साहू का अगला प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया है, क्योंकि वे एकमात्र उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। बाबूलाल मरांडी और रघुबर दास जैसे वरिष्ठ नेताओं के व्यापक समर्थन से उनका निर्विरोध निर्वाचन पार्टी में सर्वसम्मति को दर्शाता है, जिसकी औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को होगी।

नई दिल्ली 13 जनवरी (एजेंसी)आदित्य साहू झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बाद उनका चुनाव लगभग सुनिश्चित हो चुका है। औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को की जाएगी। मंगलवार को राज्य भाजपा कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया में दिन भर काफी चहल–पहल रही, लेकिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच निधारित समय में केवल एक ही नामांकन दाखिल किया गया। दोपहर लगभग 1 बजे, साहू ने वरिष्ठ पार्टी नेताओं की उपस्थिति में पार्टी के नामित चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री जोएल ओरांव के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया।नामांकन का प्रस्ताव पार्टी नेतृत्व के एक व्यापक वर्ग द्वारा किया गया था, जिसमें वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री करिया मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, समीर ओरांव, अर्जुन मुंडा और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। मैदान में कोई अन्य उम्मीदवार न होने के कारण साहू का पदोन्नति होना एक औपचारिकता ही मानी जा रही है। मीडिया को जानकारी देते हुए जोएल ओरांव ने बताया कि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामों की घोषणा 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे की जाएगी। साहू वर्तमान में पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।संगठनात्मक चुनाव में राष्ट्रीय परिषद के लिए भी मतदान हुआ, जहां 21 उपलब्ध सीटों के लिए 21 नामांकन दाखिल किए गए, जिससे यह चुनाव भी निर्विरोध हो गया। इन पदों के परिणाम भी 14 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। राज्य चुनाव प्रभारी प्रदीप वर्मा ने कहा कि पार्टी अपनी आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रही है, जिसमें नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापस लेने की अवधि शामिल है। इन चरणों के लगभग पूरा होने के साथ, पिछले वर्ष शुरू हुई संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है। राज्य पार्टी कार्यालय के वरिष्ठ नेताओं ने साहू को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

अरविन्द केजरी को राहत नहीं
संजय सिंह के साथ ही चलेगा मानहानि का केस

न्यायमूर्ति एमआर मेंगडे ने आदेश सुनाते हुए कहा आवेदन खारिज किया जाता है। इससे पहले, अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद स्थित सिटी सेशंस कोर्ट के अतिरिक्तप्रधान न्यायाधीश मनीष प्रद्युमन पुरोहित के 15 दिसंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 23 सितंबर, 2023 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग वाली उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।

नई दिल्ली 13 जनवरी (एजेंसी)दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से अलग सुनवाई की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। यह मामला आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री की डिग्री की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने से संबंधित है। न्यायमूर्ति एमआर मेंगडे ने आदेश सुनाते हुए कहा आवेदन खारिज किया जाता है। इससे पहले, अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद स्थित सिटी सेशंस कोर्ट के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश मनीष प्रद्युमन पुरोहित के 15 दिसंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 23 सितंबर, 2023 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग वाली उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट न्यायालय में अर्जी दाखिल कर अपील की थी कि याचिकाकर्ता का मुकदमा दूसरे आरोपी (आप नेता संजय सिंह) के मुकदमे से अलग चलाया जाए, क्योंकि दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर एक ही शिकायत पर मुकदमा चलाना न्याय के हित में नहीं होगा। केजरीवाल ने सत्र न्यायालय में तर्क दिया था कि दोनों आरोपियों पर एक साथ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अर्जी खारिज करना अवैध था, क्योंकि दोनों आरोपियों के खिलाफ लेन–देन और आरोप अलग–अलग हैं।

जना नायकन विवाद के बीच टीवीके का बड़ा ऐलान
तमिलनाडू गठबंधन पर सिर्फ विजय लेंगे फैसला

टीवीके महासचिव ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर अंतिम निर्णय पार्टी प्रमुख विजय लेंगे, जो सीबीआई पूछताछ के बाद चेन्नई लौट रहे हैं। पार्टी ने अपने वैचारिक रुख को लेकर स्पष्टता जताते हुए कहा कि नेता का फैसला ही सर्वोपरि होगा।

नई दिल्ली 13 जनवरी (एजेंसी)सीबीआई द्वारा पूछताछ के बाद टीवीके प्रमुख विजय के चेन्नई लौटने का इंतजार करते हुए, पार्टी के महासचिव सीटीआर निर्मल कुमार ने मंगलवार को कहा कि पार्टी अपने वैचारिक रुख को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है और आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन की स्थिति में नेता निर्णय लेंगे। दिल्ली से विजय के लौटने का इंतजार करते हुए चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए टीवीके सचिव ने कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमारा गठबंधन कैसा होगा, इस बारे में हम बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमने अपना वैचारिक रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। अगर गठबंधन की बात होती है, तो हम आपको सूचित करेंगे।कुमार ने आगे कहा कि गठबंधन की स्थिति में हमारे नेता निर्णय लेंगे। विजय की आखिरी फिल्म श्जना नायकनश के बारे में बात करते हुए, जिसकी रिलीज प्रमाणन में देरी के कारण स्थगित हो गई थी, पार्टी नेता ने कहा कि वे चाहते हैं कि फिल्म श्शांतिपूर्ण ढंग से रिलीजश हो और रिलीज होने के बाद वे स्थिति को स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा, ष्हम उन सभी लोगों और नेताओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने फिल्म की रिलीज का समर्थन किया। यह हमारे नेता की आखिरी फिल्म है। भावनात्मक रूप से, हमारे सभी पार्टी कार्यकर्ता, पूरा तमिलनाडु और सभी प्रशंसक चाहते थे कि यह फिल्म शांतिपूर्वक रिलीज हो, लेकिन यह मामला अदालत में लंबित है। फिल्म रिलीज होने के बाद हम स्थिति को स्वीकार कर लेंगे।इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिल्म की रिलीज का समर्थन किया, जबकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म के प्रमाणन को रोके जाने के बाद केंद्र सरकार पर हमला करते हुए इसे तमिल संस्कृति पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तमिल लोगों की आवाज को दबाने में सफल नहीं होंगे। कांग्रेस नेता ने ग पर लिखा, ष्सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा श्जना नायकनश को रोकने का प्रयास तमिल संस्कृति पर हमला है। मोदी, आप तमिल लोगों की आवाज को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे।ष

अन्नामलाई का डीएमके पर बड़ा हमला
कहा- वादे पूरे न कर तमिलनाडू की जनता को दिया धोखा

तेनकासी जिले के वासुदेवनल्लूर में भव्य पोंगल उत्सव मनाते हुए अन्नामलाई ने कहा कि शेनबागवल्ली बांध के जीर्णोद्धार की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी नहीं हुई है, जबकि खनिज संसाधनों की अवैध तस्करी बढ़ रही है।

नई दिल्ली 13 जनवरी (एजेंसी)भारतीय जनता पार्टी के नेता के. अन्नामलाई ने मंगलवार को डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा न करके उन्हें श्धोखाश दिया है। तेनकासी जिले के वासुदेवनल्लूर में भव्य पोंगल उत्सव मनाते हुए अन्नामलाई ने कहा कि शेनबागवल्ली बांध के जीर्णोद्धार की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी नहीं हुई है, जबकि खनिज संसाधनों की अवैध तस्करी बढ़ रही है।मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार की श्प्रशासनिक विफलताश को उजागर करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर निष्क्रियता के कारण डीएमके के एक पदाधिकारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अन्नामलाई ने ग पर पोस्ट किया, "डीएमके सरकार शेनबागवल्ली बांध के जीर्णोद्धार की लंबे समय से चली आ रही मांग सहित जनता से किए गए वादों को पूरा न करके उन्हें धोखा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, केंद्र में स्थित भाजपा सरकार ने पुलियानकुडी नींबू को भौगोलिक संकेत (ळमवहतंचीपबंस प्दकपबंजपवद) की मान्यता दे दी है।"अवैध तस्करी के बारे में बात करते हुए, अन्नामलाई ने कहा कि तेनकासी से केरल में खनिज संसाधनों की अवैध तस्करी बढ़ रही है। डीएमके सरकार की इस पर अंकुश लगाने में असमर्थता से डीएमके के एक पदाधिकारी इतने निराश हुए हैं कि उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है, जो मुख्यमंत्री की प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। अन्नामलाई ने जनता से एकता का आह्वान किया और कहा कि तेनकासी के लोगों को मिट्टी से जड़े राष्ट्रवादी विचारक को विधानसभा में भेजना चाहिए।उन्होंने पोंगल पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सूर्य और पंच तत्वों का सम्मान करने वाले इस भव्य पोंगल पर्व पर, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से सभी प्राणियों के कल्याण और समृद्धि की हार्दिक कामना करता हूं। इससे पहले, तिरुनेलवेली जिले के डीएमके नेता चंद्रशेखर ने खनिज तस्करी पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी की सदस्यता त्याग दी।

असम में मियां राजनीति पर घमासान
सीएम हिमंता सरमा बोले- कांग्रेस बदल रही है डेमोग्राफी

नई दिल्ली 13 जनवरी (एजेंसी)मुख्यमंत्री हिमंता सरमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ऊपरी असम के प्रमुख जिलों की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने की योजना बना रही है। उन्होंने शिवसागर और तिनसुकिया को धुबरी में बदलने की हालिया टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ (एएमएसयू) के पूर्व अध्यक्ष रेजाउल करीम सरकार ने शिवसागर को ध ुबरी, बराक घाटी को शिवसागर और तिनसुकिया को धुबरी में बदलने की बात कही थी। उनका दावा था कि ऐसे बदलाव असम को आगे ले जाने में सहायक होंगे।इस टिप्पणी पर तत्काल तीखी प्रतिक्रिया हुई, खासकर ऊपरी असम में। शिवसागर को ऐतिहासिक रूप से अहोमों का गढ़ माना जाता है, जबकि धुबरी को व्यापक रूप से बंगाली मुस्लिम बहुल जिला माना जाता है। सरकार ने कहा, ष्हम भय में जी रहे हैं,ष और आगे कहा कि वह गौरव गोगोई के साथ श्सेनापतिश (कमांडर) के रूप में मजबूती से खड़े रहेंगे और असम से हिमंता बिस्वा सरमा को बाहर निकालकर इस घ्चिंता को समाप्त करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें असम और उसके समाज एवं संस्कृति को बचाना है। मुझे विश्वास है कि मैं असम के सभी समुदायों और अपने पिछड़े समुदाय का एक मंच पर लाऊंगा... और एक–दूसरे के सहयोग से हम असम को आगे ले जाएंगे।मुख्यमंत्री हिमंता सरमा ने कहा कि ये टिप्पणियां प्रमुख जिलों की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने के पार्टी के इरादे की खुली घोषणा के समान हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी पर असम के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने–बाने को खतरे में डालने वाले एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सरमा ने कहा कि कांग्रेस के मंच से आज दिए गए बयान से साफ पता चलता है कि उन्होंने शिवसागर और तिनसुकिया जैसे जिलों को 'मिया' की भूमि में बदलने का अपना इरादा खुलेआम जाहिर कर दिया है।सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर भी निशाना साधा और कहा कि वे उस कार्यक्रम में मौजूद थे। सरमा ने कहा कि गौरव गोगोई उस समय मौजूद थे जब यह बयान दिया गया था।

बिहार में बुजुर्गों को अब घर पर मिलेगी जमीन- फ्लैट की रजिस्ट्री की सुविधाः नीतीश कुमार

नई दिल्ली 13 जनवरी (एजेंसी)बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य के 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को उनके घर पर ही जमीन या फ्लैट की निबंधन (रजिस्ट्री) सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान किया। यह सुविधा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा संचालित चलंत निबंधन इकाई (मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट) के माध्यम से निश्चित समय–सीमा के भीतर प्रदान की जाएगी, जिसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह नयी व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि कई बार यह देखा गया है कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर उन्हें सहूलियत देने और अनावश्यक परेशानियों से बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने के इच्छुक लोगों को कई बार संबंधित भूमि की अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसे ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री से पूर्व भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी क्रेता और विक्रेता दोनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है।

जम्मू कश्मीर में आतंकी तंत्र पर बड़ा प्रहार
एलजी मनोज सिन्हा ने 5 सरकारी कर्मचारियों को किया टरमिनेट

जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी संबंधों के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ब) के तहत बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई सरकारी तंत्र से आतंकवाद के प्रभाव को खत्म करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत 2021 से अब तक 85 से अधिक कर्मचारी हटाए जा चुके हैं।

नई दिल्ली 13 जनवरी (एजेंसी)सरकारी तंत्र में व्याप्त आतंकी गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कथित आतंकी संबंधों के आरोप में पांच सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि इन सक्रिय सहयोगियों को आतंकी संगठनों और पाकिस्तान आईएसआई द्वारा सरकारी तंत्र में शामिल किया गया था। उन्होंने पिछले कई दशकों में प्रशासन में घुसपैठ करके सरकारी तंत्र को कमजोर किया और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला।इन पांच कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) के तहत बर्खास्त किया गया। बर्खास्त कर्मचारियों में एक शिक्षक भी शामिल है, जो जांचकर्ताओं के अनुसार, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर–ए–तैबा (एलईटी) के लिए काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक, उसे अप्रैल 2022 में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पुलिस के खिलाफ अपनी योजना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अन्य कर्मचारियों में हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) से कथित तौर पर जुड़ा एक लैब तकनीशियन, लश्कर–ए–तैबा से जुड़ा एक सहायक लाइनमैन, एचएम से कथित तौर पर जुड़ा वन विभाग का एक फील्ड वर्कर और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक ड्राइवर शामिल हैं।सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने बताया, ष्हालांकि, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2021 में आतंकी तंत्र को बेनकाब करने और उसकी नींव तोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। वित्तपोषकों से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक, सभी तत्वों के खिलाफ उनकी निर्णायक और व्यापक कार्रवाई ने आतंकी ढांचे को काफी हद तक ध्वस्त कर दिया।ष 2021 से, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने 85 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं जो आतंकवादी समूहों के लिए काम करते पाए गए थे।सूत्रों ने संकेत दिया कि यह कार्रवाई व्यवस्था से आतंकवादी प्रभाव को खत्म करने के उद्देश्य से की गई है।

सम्पादकीय

जानलेवा सड़कें

देश में आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार और समाज के स्तर पर चिंताएं तो व्यक्त की जाती हैं लेकिन इन्हें रोकने के लिये कारगर उपाय सिरे चढ़ते नजर नहीं आते। इस बारे में बार–बार वायदे किए जाते हैं, वहीं सुधार के लिये टुकड़ों–टुकड़ों में हस्तक्षेप किया जाता है। फलतरू परिणाम वही ढाक के तीन पात रहता है। यह आंकड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में हर साल 1.6 लाख से अधिक मौतें सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। विडंबना देखिए कि किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के मुकाबले सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा लोगों की जान ले लेती हैं। हाल ही में सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के लिये किए गए सर्वेक्षण में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। संस्था द्वारा वर्ष 2023 व 2024 में 100 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं पर किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि शाम छह बजे से रात नौ बजे तक समय सड़क हादसों के लिये सबसे घातक होता है। इसके अलावा दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिये 18 सड़क गलियारों की पहचान की गई है, जिनमें सर्वेक्षण अवधि में सबसे अधिक मौते हुई थीं। इसके साथ ही दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील सौ जिलों में ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया है। निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य पहल है। यह जानते हुए कि दुर्घटना रोकने के लिये सामान्य सलाह और एक समान नीतियां लक्ष्य हासिल करने में विफल रही हैं। यकीनी तौर पर दुर्घटना उन्मुख क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप बदलाव लाने के लिये बेहतर दृष्टिकोण साबित हो सकता है। बहुत संभव है कि एक खराब ढंग से डिजाइन किया गया मोड़, सड़क पर पर्याप्त रोशनी का न होना, प्रवर्तन में शिथिलता तथा ड्राइविंग में लापरवाही की आदतें, किसी क्षेत्र या जिला विशेष में सड़क दुर्घटनाओं की वजह हो सकती है। निश्चित तौर पर उच्च मृत्यु दर वाले गलियारों का मानचित्रण अधिकारियों को, उन क्षेत्रों में इंजीनियरिंग सुधार, प्रवर्तन और आपातकालीन प्रतिक्रिया बल तैनात करने में सहायक हो सकता है। निस्संदेह, साक्ष्य और अतीत के अनुभव बताते हैं कि लक्षित प्रवर्तन बेहतर परिणाम दे सकता है। बंगलुरू का अनुभव बताता है कि लक्षित प्रयासों से वहां लगातार दूसरे वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के बावजूद मृत्यु दर में कमी आई है। जो इन प्रयासों की सार्थकता को दर्शाता है। निस्संदेह, अन्य शहरों को भी डेटा आधारित पुलसिंग, सीसीटीवी निगरानी और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिये इस मॉडल को अपनाना होगा। इसमें दो राय नहीं कि केंद्र सरकार की योजना तभी सफल होगी, जब वह पहचान और प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर काम करे। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी पिछली कोशिशें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल न होने से विफल रही हैं। इन सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिये निरंतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, कार्यान्वयन एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के साथ ही परिणामों का नियमित ऑडिट करना आवश्यक है। इस बाबत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों को कार्रवाई करने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिए। वैसे सिर्फ राजमार्गों पर ही ध्यान केंद्रित करने के भी कई खतरे हैं। यह जानते हुए कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क नेटवर्क का मुश्किल से 2 से तीन प्रतिशत हिस्सा ही है। लेकिन ट्रैफिक की गति की तीव्रता के चलते इन पर होने वाली मौतों की संख्या कहीं ज्यादा है। साल 2025 की पहली छमाही ही में करीब छब्बीस हजार से अधिक मौतें हुई हैं। वास्तव में शहरी सड़कें, जहां पैदल यात्री,साइकिल चालक और दोपहिया वाहन चालकों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या का बड़ा हिस्सा है, वे अक्सर उपेक्षित रह जाती हैं। इन सड़कों को बेहतर बनाने के लिये निवेश बढ़ाए जाने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षित डिजाइन तैयार करने, वाहनों की गति का प्रबंधन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट बांधना सुनिश्चित करने तथा आपातकालीन देखभाल व्यवस्था को साथ–साथ लागू करने की भी आवश्यकता है।

पल्लवी की मौत से उपजे सवाल

हमारे जिन शिक्षण संस्थानों को बच्चों के भीतर छिपी असीमित क्षमताओं योग्यता को तराश कर कुशल और जिम्मेदार नागरिक बनाने का दायित्व निभाना चाहिए था, आज उनकी दुर्दशा सवालों के घेरे में है क्योंकि बहुत सारे शिक्षण संस्थान छात्र छात्राओं के मानसिक शारीरिक व यौन उत्पीड़न के अड्डे बन गए हैं और जिम्मेदार लोग इन संस्थानों में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सख्त एक्शन लेने के स्थान पर उन पर परदा डालने में जुट जाते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सरकारी डिग्री कॉलेज की 19 वर्षीय दलित छात्रा पल्लवी की इलाज के दौरान मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में एक प्रोफेसर सहित तीन लोगों के खिलाफ रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गये हैं। शिकायत में कहा गया है कि गत वर्ष 18 सितम्बर को उसकी बेटी को उक्त 3 छात्राओं ने बुरी तरह पीटा जबकि उस दौरान संबंधित प्रोफैसर पीड़ित छात्रा के साथ अश्लील काम करने में व्यस्त था। यह सिर्फ एक दलित बेटी के साथ हुए अन्याय का इकलौता मामला नहीं है। सवाल है कि आखिर एक होनहार छात्रा को मौत के मुंह में धकेलने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे उच्च शिक्षा संस्थान उत्पीड़न के अड्डे में क्यों तब्दील हो रहे हैं? शिक्षकों की संवेदनशीलता और नैतिकता कहां गायब हो रही है?

पुलिस थाना धर्मशाला में दर्ज शिकायत में बताया गया है कि मृतक छात्रा डिग्री कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। आरोप है कि 18 सितंबर को कॉलेज की कुछ छात्राओं ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दीं। एफआईआर में मृतक छात्रा के परिजनों ने कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगाए हैं। परिजनों के बताया कि कॉलेज प्रोफेसर की इन हरकतों के बाद छात्रा गहरे सदमे में चली गई। धीरे–धीरे उसकी हालात बिगड़ती गई। छात्रा के परिजनों के अनुसार विभिन्न अस्पतालों में इलाज के बाद 26 दिसंबर को लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं छात्रा की मौत के बाद दर्ज हुई एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि कॉलेज की कुछ लड़कियां उसके साथ मारपीट करती थी।पुलिस के अनुसार, यह मामला पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 18 सितंबर 2025 को कॉलेज की तीन सीनियर छात्राओं–हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने उनकी बेटी के साथ रैगिंग की और उसके साथ मारपीट की। इसके साथ ही कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर पीड़िता के साथ अशोभनीय व्यवहार और यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए गए हैं।

छात्रा ने मरने से पहले इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया था। पुलिस के मुताबिक लड़की के साथ यह घटनाक्रम 18 सितंबर को शुरू हुआ। खुद के साथ हुए घटनाक्रम से वह डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद लगातार उसकी तबीयत खराब होती गई और अलग–अलग अस्पतालों में उसका इलाज चला लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। इसी बीच 26 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 6 बजे पल्लवी की मौत हो गई।

आरोप है कि तीन सीनियर छात्राओं ने उसे रैगिंग का शिकार बनाया और एक कॉलेज प्रोफेसर ने उसका यौन उत्पीड़न किया। अब छात्रा का एक कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने कॉलेज में झेली गई आपबीती बता रही है। छात्रा ने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि अशोक सर पीछे पड़ जाते थे और अजीब–अजीब हरकतें करते थे। छात्रा ने वीडियो के जरिए कॉलेज प्रोफेसर पर यह भी आरोप लगाया की अशोक सर मुझे गलत जगह टच करते थे। इतना नहीं वीडियो में छात्रा ये भी कहती सुनाई दे रही है कि आपको कैसे बताऊं, मैं उठकर बताउंगी लेकिन छात्रा ठीक नहीं हो पाई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

दूसरी ओर छात्रा के मरने के बाद एक वीडियो और सामने आया है, जिसमें छात्रा की मां और पिता उससे पूछते नजर आए कि कॉलेज में तुम्हारे साथ क्या–क्या होता है? इस पर छात्रा कहती है कि लड़कियां मारती थीं और पढ़ने नहीं देती थीं। साथ ही छात्रा ने यह भी बताया कि कॉलेज में लड़कियों ने उसे सिर पर भी मारा था। इसके अलावा लड़कियां मुझे पढ़ने भी नहीं देती थीं। छात्रा के फेल होने पर उसे लड़कियां तंग करती थीं।

पूरे मामले को लेकर यूजीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग के आरोपों के बाद एक छात्रा की मौत की जांच के आदेश दिए हैं।

यूजीसी ने घटना की जांच के लिए एक फैक्ट–फाइंडिंग कमेटी बनाई है। एक सीनियर यूजीसी अधिकारी ने कहा कि यूजीसी ने धर्मशाला के सरकारी डिग्री कॉलेज में एक छात्रा की दुखद मौत का गंभीर संज्ञान लिया है। यूजीसी एंटी–रैगिंग हेल्पलाइन ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर खुद ही शिकायत दर्ज की है, जिसमें रैगिंग के कारण आत्महत्या का आरोप लगाया गया है जबकि कॉलेज अधिकारियों ने कहा है कि यह मामला मौत का है, आत्महत्या का नहीं।अधिकारी ने आगे कहा कि पुलिस जांच चल रही है और यूजीसी ने घटना की जांच के लिए एक फैक्ट–फाइंडिंग कमेटी बनाई है। यूजीसी भरोसा दिलाता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। पुलिस के अनुसार कॉलेज के तीन छात्रों पर रैगिंग और जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही एक प्रोफेसर पर भी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है।

एसपी कांगड़ा अशोक रतन ने बताया कि मामले की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। यह मामला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115(2), 3(5) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत दर्ज किया है। एसपी ने यह भी कहा कि छात्रा का बड़े अस्पताल में इलाज हो रहा था।देश के शिक्षण संस्थानों में लगातार शैक्षिक स्तर में गिरावट आ रही है वहीं हर साल पचास से अधिक छात्र छात्राओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के साथ दीक्षा की जरूरत है वहीं शिक्षकों में पेशेगत योग्यता के साथ–साथ नैतिकता और सदाचार का कठोर प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। मौजूदा घटना भी इस जरूरत को संकेत करती है। वहीं जो शिक्षक स्वयं असंवेदनशील और कदाचार मे लिप्त हैं। उनसे प्रेरित होकर अन्य छात्र छात्राओं द्वारा भी सज्जन और चरित्रवान छात्र छात्राओं का शारीरिक मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। इस छात्रा की मौत की उच्च स्तरीय जांच कर सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। (हिफी)

खुशियों का संदेशवाहक पर्व है लोहड़ी

योगेश कुमार गोयल

हरियाणा व पंजाब में जिस घर में नई शादी हुई हो अथवा संतान (लड़के) का जन्म हुआ हो या शादी की पहली वर्षगांठ का मौका हो, ऐसे परिवारों में लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। इन परिवारों में लोहड़ी के अवसर पर उत्सव जैसा माहौल होता है। आसपास के लोगों के अलावा रिश्तेदार भी इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं।उत्तर भारत में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है लोहड़ी। यह ऐसा त्यौहार है, जो आधुनिक युग के व्यस्तता भरे माहौल में सुकून भरे कुछ पल लेकर आता है और लोग सारी व्यस्तताएं भूलकर भरपूर जोश और उल्लास के साथ इस पर्व का भरपूर आनंद लेते हैं। पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में तो लोहड़ी पर्व मकर संक्रांति के रूप में ही मनाया जाता है। सिंधी समाज में भी मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी के रूप में 'लाल लाही' नामक पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी को लेकर कुछ लोककथाएं भी प्रचलित हैं। मान्यता है कि कंस ने इसी दिन लोहिता नामक एक राक्षसी को श्रीकृष्ण का वध करने के लिए भेजा था, जिसे श्रीकृष्ण ने खेल–खेल में ही मार डाला था और उसी घटना की स्मृति में यह पर्व मनाया जाने लगा। लोहड़ी पर अग्नि प्रज्जवलित करने के संबंध में एक लोककथा यह भी है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के योगाग्नि दहन की स्मृति में ही इस दिन अग्नि प्रज्जवलित की जाती है। लोहड़ी को लेकर सर्वाधिक प्रचलित कथा दुल्ला भट्टी नामक डाकू से संबंधित रही है, जिसे 'पंजाबी रॉबिनहुड' का दर्जा प्राप्त है।

जिस प्रकार होली जलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार लकडिघ्यां एकत्रित कर लोहड़ी के अवसर पर अलाव जलाये जाते हैं और अग्नि का तिलों से पूजन किया जाता है। जिस दिन यह पर्व मनाया जाता है, उस दिन कड़ाके की ठंड होती है और उत्तर भारत में अधिकांश जगहों पर घने कोहरे के बीच तापमान प्रायः शून्य से पांच डिग्री के बीच होता है लेकिन इतनी ठंड के बावजूद इस पर्व के प्रति लोगों का उत्साह देखते बनता है। लोहड़ी के पावन अवसर पर लोग घरों के बाहर अलाव जलाकर यह पर्व धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व का संबंध उस उत्सव से भी माना गया है, जिसमें सर्दी को अलविदा कहते हुए सूर्यदेव का आव्हान करते हुए कहा जाता है कि वह इस माह अपनी किरणों से पृथ्वी को इतना गर्म कर दे कि ठंड से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे और लोग आसानी से सर्दी के मौसम का मुकाबला कर सकें। माना जाता है कि इसी दिन से सर्दी कम होने लगती है। लोग अपने घरों के बाहर अलाव जलाकर ठंड से बचाव करने के साथ–साथ अग्नि की पूजा भी करते हैं ताकि उनके घर में अग्निदेव की कृपा से सुख–समृद्धि का साम्राज्य स्थापित हो सके। हरियाणा व पंजाब में जिस घर में नई शादी हुई हो अथवा संतान (लड़के) का जन्म हुआ हो या शादी की पहली वर्षगांठ का मौका हो, ऐसे परिवारों में लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। इन परिवारों में लोहड़ी के अवसर पर उत्सव जैसा माहौल होता है। आसपास के लोगों के अलावा रिश्तेदार भी इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। घर में अथवा घर के बाहर खुले स्थान पर अग्नि जलाकर लोग उसके इर्द–गिर्द इकट्ठे होकर आग सेंकते हुए अग्नि में मूंगफली, गुड़, तिल, रेवड़ी, मक्का के भुने हुए दानों इत्यादि की आहूति देते हैं और रातभर भंगड़ा, गिद्धा करते हुए मनोरंजन करते हैं तथा बधाई देते हैं।लोहड़ी का संबंध सुन्दरी नामक एक ब्राह्मण कन्या और दुल्ला भट्टी नामक कुख्यात डाकू से जोड़कर देखा जाता रहा है। दुल्ला भट्टी अमीरों का धन लूटकर निर्धनों में बांट दिया करता था। कहा जाता है कि गंजीबार क्षेत्र, जो इस समय पाकिस्तान में है, में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी सुन्दरी नामक एक बहुत खूबसूरत बेटी थी, जो इतनी खूबसूरत थी कि उसके सौन्दर्य की चर्चा गली–गली में होने लगी थी। जब उसके बारे में गंजीबार के राजा को पता चला तो उसने ठान लिया कि वह सुन्दरी को अपने हरम की शोभा बनाएगा। तब उसने सुन्दरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दे। इसके लिए ब्राह्मण को तरह–तरह के प्रलोभन भी दिए मगर ब्राह्मण अपनी बेटी को राजा की रखैल नहीं बनाना जाता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे? जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रहने वाले कुख्यात डाकू दुल्ला भट्टी का ख्याल आया, जो गरीबों व शोषितों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। घबराया ब्राह्मण अपनी बेटी सुन्दरी को लेकर उसी रात उसके पास पहुंचा और विस्तार से सारी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुन उसे सांत्वना दी और रात को ही एक योग्य ब्राह्मण लड़के की तलाश कर सुन्दरी को अपनी ही बेटी मानकर उसका कन्यादान अपने हाथों से करते हुए उस युवक के साथ सुन्दरी का विवाह कर दिया।गंजीबार के राजा को इसकी जानकारी मिली तो वह बौखला उठा। उसके आदेश पर उसकी सेना ने दुल्ला भट्टी के ठिकाने पर धावा बोल दिया किन्तु दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने राजा को बुरी तरह धूल चटा दी। दुल्ला भट्टी के हाथों गंजीबार के शासक की हार होने की खुशी में गंजीबार में लोगों ने अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़ा डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुन्दरी व दुल्ला भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। लोहड़ी से पहले ही बच्चे इकट्ठे होकर लोहड़ी के गीत गाते हुए घर–घर जाकर लोहड़ी मांगने लगते हैं। इस दिन उत्सव के लिए लकडिघ्यां व उपले एकत्र करने के लिए भी बच्चे कई दिन पहले ही जुट जाते हैं। वैसे समय बीतने के साथ–साथ अब घर–घर से लकडिघ्यां मांगकर लाने की परम्परा समाप्त होती जा रही है। बहुत से स्थानों पर लोग अब लकडिघ्यां व उपले बच्चों के जरिये मांग–मांगकर एकत्र कराने के बजाय खरीदने लगे हैं।

लोहड़ी के दिन सुबह से ही रात के उत्सव की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं और रात के समय लोग अपने–अपने घरों के बाहर अलाव जलाकर उसकी परिक्रमा करते हुए उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी, चिड़वा, पॉपकॉर्न इत्यादि डालते हैं और माथा टेकते हैं। उसके बाद अलाव के चारों ओर बैठकर आग सेंकते हैं। तब शुरू होता है गिद्दा और भंगड़ा का मनोहारी कार्यक्रम, जो रात्रि में देर तक चलता है और कहीं–कहीं तो पूरी–पूरी रात भी चलता है। अगले दिन प्रातः अलाव ठंडा होने पर मौहल्ले के सभी लोग इसकी राख को 'ईश्वर का उपहार' मानते हुए अपने–अपने घर ले जाते हैं। यह पर्व सही मायने में समाज में प्रेम व भाईचारे की अनूठी मिसाल कायम करता है।

घरेलू महिलाएं खुद न करें अपनी खुशी की हत्या

प्रज्ञा पांडेय

आज का समय फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का है। हर व्यक्ति बोल रहा है, लिख रहा है, दिख रहा है। प्रतिभा को मंच मिल रहा है, अभिव्यक्ति को विस्तार मिल रहा है। लेकिन इसी शोर के बीच एक तबका ऐसा है, जो आज भी चुप है–या यूं कहें कि चुप करा दिया गया है।

मैं उन स्त्रियों की बात कर रही हूं, जिनका पूरा जीवन केवल नर्म, गोल और गर्मा–गर्म रोटियां बनाते–बनाते ठंडा पड़ गया। 40 साल पहले हालात अलग थे, तब विकल्प नहीं थे। लेकिन आज भी वही जीवन जीना, वही तर्क देना, यह मजबूरी नहीं, आदत बन चुकी है। स्पष्ट कर दूं–रोटी बनाना कोई अपराध नहीं, अपराध यह है कि आप खुद को केवल रोटी बनाने की मशीन में बदल दें। 'रोटी बनाना' और 'रोटी भी बनाना', इन दोनों में वही अंतर है जो जिंदा रहने और जीने में होता है। कटु सत्य यह है कि रोटी को एकदम गोल बनाने की जिद में आपने अपने व्यक्तित्व की सारी धार कुंद कर दी। दूसरों की थाली गर्म रखने में आप खुद ठंडी पड़ गईं और यह कोई त्याग नहीं, यह आत्म–उपेक्षा है। आप सबको उतनी ही गर्म रोटी खिलाइए, जितनी आप स्वयं भी उनके साथ बैठकर खा सकें। वरना याद रखिए, जो औरत खुद नहीं खाती, उसे कोई खिलाने नहीं आता। आपने अपनी पूरी ऊर्जा फर्श चमकाने, रसोई संभालने और चूल्हे में झोंक दी। अब जब खुद को पीछे छूटा पाती हैं, तो अपनी कुंठा नई पीढ़ी, कामकाजी महिलाओं या बहुओं पर थोप देती हैं। यह असंतोष का समाधान नहीं, सिर्फ उसका बदसूरत रूप है। अब दूसरों से जलना बंद कीजिए। सच तो यह है कि जलन उनकी नहीं, अपनी अधूरी संभावनाओं की है। ठहरिए और खुद से पूछिए–

क्या मैं आज वही हूं, जो मैं हो सकती थी? अगर जवाब 'नहीं' है, तो दोष दुनिया को नहीं, अपनी प्राथमिकताओं को दीजिए। जिन कारणों ने आपको रोका, उन्हें रोने की सूची से हटाकर जीवन की 'बी–लिस्ट' में डाल दीजिए। कड़वा सच यह है कि दुनिया आपको आपके त्याग से नहीं, आपकी उपलब्धियों से पहचानती है। आपने कितना सहा, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि परिवार को भी नहीं। बच्चे बड़े होते ही व्यस्त हो जाते हैं और पति की व्यस्तता तो वर्षों पुराना बहाना है।अक्सर देखा जाता है कि रोटी ठंडी हो रही हो और आप आवाज दें, तो जवाब मिलता है–'आपको तो खाने की ही पड़ी है।' सोचिए, जिस खाने के लिए आपने अपने सपने फ्रीजर में रख दिए, उसकी कीमत किसी की नजर में क्या है। इसलिए अब वक्त है कि 'रोटी ही बनाना' को 'रोटी भी बनाना' में बदला जाए। जीवन कोई गैस सिलैंडर नहीं है, जो जब चाहे बदल लिया जाए। जो करना है, अभी कीजिए। क्योंकि भविष्य में न आपका बेटा अपनी पत्नी को सिर्फ रोटी बनाने देगा और न आपकी बेटी खुद को चूल्हे तक सीमित करेगी। तब उन्हें कोसने से अच्छा है कि आज खुद को बदला जाए। खाना बनाइए, घर संभालिए लेकिन इसके बाद खुद को भी समय दीजिए। कुछ रचिए, कुछ सीखिए। जब आप खुद को गंभीरता से लेंगी, तब परिवार भी आपको हल्के में लेना बंद कर देगा। और हां! जिस दिन आप रसोई के समय सबके पीछे भागना बंद करेंगी, उसी दिन सब समय पर खाने आने लगेंगे। सम्मान मांगना नहीं पड़ता, सीमाएं तय करनी पड़ती हैं। यह लेख घर–परिवार छोडने की वकालत नहीं करता। यह सिर्फ इतना कहता है कि घर बचाने के चक्कर में खुद को मत खोइए। किसी भूली हुई हॉबी को फिर से उठाइए–लिखिए, पढिए, सीखिए, कमाइए या बस खुद के लिए जिएं। शुरुआत में तालियां नहीं मिलेंगी लेकिन याद रखिए, जो औरत खुद के लिए खड़ी हो जाती है, उसे गिराना आसान नहीं होता। और अंत में– जीवन जीना कोई मजबूरी नहीं, यह एक कला है, एक तैयारी है। खुद को खुश रखना कोई स्वार्थ नहीं, यह आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है।

कार्ययोजना के हाशिये से निर्णय के केंद्र तकरू प्रगति और मिजोरम की रेल अवसंरचना

श्री वरूण अधिकारी, मुख्य इंजीनियरिंग भूविज्ञानी

कार्ययोजना के हाशिये से निर्णय के केंद्र तकरू प्रगति और मिजोरम की रेल अवसंरचना

– श्री वरूण अधिकारी, मुख्य इंजीनियरिंग भूविज्ञानी

जब मैं 2015 में बैराबी–सैरांग रेलवे परियोजना में शामिल हुआ, तो मुझे लगता था कि यह देश के ऐसे हिस्से में कदम रखने जैसा है, जिस पर शायद ही कभी राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया गया हो। यह सफर खुद ही अपनी कहानी कहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग–154, जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग–06 कहा जाता है, एकमात्र पहुंच मार्ग था, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और भरोसे के लायक नहीं था। भारी ट्रक अक्सर कई दिनों तक फंसे रहते थे और निकटवर्ती स्थानों की यात्रा हिचकोलों से भरी होती थी। आस–पास की पहाड़ियाँ छोटी, कमजोर और अस्थिर थीं, जिनका आकार तीव्र वर्षा और निरंतर ढलान गति के कारण बदलता रहता था। कागज पर, परियोजना ऐतिहासिक थी, राष्ट्रीय नेटवर्क से मिजोरम का पहला रेल–परिवहन संपर्क, जो पहाड़ों, तीव्र ढलान और गहरी घाटियों को काट कर तैयार किया जा रहा था।

हालाँकि, जमीनी स्तर पर प्रगति बहुत धीमी थी। सामग्री की अनुपलब्धता, श्रम की कमी, परिवहन में विलंब, स्थानीय बाधाएं और लगातार स्थगित निर्णयों के कारण कार्यस्थल पर काम न होना आम बात थी। एक सुरंग डिजाइन सलाहकार और भूविज्ञानी के रूप में, भूविज्ञान कार्य चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसकी गंभीरता समझी जा सकती थी। जो बात वास्तव में अधिक कठिन साबित हुई, वह थी – संस्थागत निष्क्रियता। परियोजना देश के सबसे दूर–दराज के क्षेत्र में स्थित थी। समीक्षा छिटपुट थी। निर्णय लेने का अधिकार मंत्रालयों, राज्य विभागों और एजेंसियों में बिखरा हुआ था। धीरे–धीरे, एक असहज सच्चाई स्पष्ट होने लगीरू ऐसा प्रतीत होता था कि कोई भी वास्तव में यह उम्मीद नहीं करता था कि परियोजना निकट भविष्य में पूरी होगी। फिर, शांतिपूर्वक और बिना किसी घोषणा के, पूरी प्रणाली में अचानक तेजी आयी। परियोजना कार्यालयों में एक स्पष्ट तत्परता का भाव दिखने लगा। फोन बार–बार बजने लगे। वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से कार्यस्थलों का दौरा करने लगे। लंबे समय से लंबित फाइलों को तुरंत सामने लाया गया, उनकी समीक्षा की गई और उन्हें दूसरी जगहों पर भेजा गया। बैठकें तेजी से व नियमित रूप से निर्धारित की जाने लगीं, अक्सर उन एजेंसियों को भी शामिल किया गया, जो पहले अलग–थलग रहकर काम करती थीं।

एक निजी सलाहकार के रूप में, मैं प्रशासनिक विभाग का हिस्सा नहीं था और किसी ने भी गतिविधि में आयी इस अचानक तेजी के पीछे का कारण नहीं बताया। लेकिन बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लंबे अनुभव ने मुझे संकेत की पहचान करना सिखा दिया था। यह सामान्य दबाव नहीं था। यह शीर्ष स्तर पर निरीक्षण की तैयारी थी।

जल्द ही कारण स्पष्ट हो गयारू बैराबी–सैरांग रेलवे परियोजना की समीक्षा पीएम की अध्यक्षता वाले सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति) मंच के तहत निर्धारित की गई थी। परियोजना लंबे समय तक हाशिये पर रही, लेकिन प्रगति के अंतर्गत समीक्षा से प्राधिकार व जवाबदेही तय हुई और हर लंबित मुद्दे तथा एजेंसियों के बीच अड़चनों के सम्बन्ध में वास्तविक समय पर जांच की व्यवस्था की गयी। इस बैठक के बाद निर्णय मेल खाने लगे, और प्रगति दिखाई दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार शासन अक्सर परिणाम तय करता है।

मार्च 2016 की प्रगति समीक्षा बैठक ने परियोजना के आयाम में मूलभूत बदलाव किये। इस रूपरेखा के तहत, समस्याओं की अलग–अलग जाँच नहीं की जा सकती थी और न ही उन्हें अनिश्चितकाल के लिए टाला जा सकता था। एन–एच–06 की अत्यंत खराब हालत अब रेलवे के कार्य क्षेत्र के बाहर नहीं मानी जा रही थी। स्पष्ट समयसीमा और निरंतर निगरानी के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मरम्मत और सुधार कार्य करने का निर्देश दिया गया। भूमि अधिग्रहण में देरी को अब केवल सामान्य प्रशासनिक बाधाओं के रूप में नहीं देखा जा रहा थाय मिजोरम सरकार को समाधान तेज करने का निर्देश दिया गया और प्रगति पर निगरानी रखी गई। कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को औपचारिक रूप से क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण जोखिम माना गया और उन पर कड़ी निगरानी रखी गयी।

व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि निर्णयों का समन्वय ही वह बात थी, जो सबसे अधिक ध्यान खींचती थी। प्रगति के तहत, एजेंसियां अब अलग–थलग रहकर काम नहीं कर सकती थीं। जिम्मेदारियां निर्धारित की गईं, समन्वय को अनिवार्य किया गया और अनुवर्ती कार्यों में निरंतरता लाई गयी। इसका असर तुरंत दिखा, कटकहल–बैराबी खंड को मार्च 2016 में चालू किया गया, जिससे माल ढुलाई संभव हुई और पहुंच, लॉजिस्टिक्स और योजना में सुधार हुआ।

जैसे–जैसे महीने बीतते गए, यह स्पष्ट हो गया कि प्रगति संस्थागत व्यवहार को बदल रही थी। समीक्षा अब देरी की व्याख्या करने से हटकर उन्हें हल करने पर केंद्रित हो गई और रिपोर्ट के स्थान पर तस्वीरों, समयरेखाओं और स्थल अवस्थति डेटा का उपयोग होने लगा। डिजिटल निगरानी यह सुनिश्चित करती थी कि एक बार उठाए गए मुद्दे तब तक चर्चा में बने रहें जब तक कि उनका समाधान न हो जाए। इस अनुशासन से पूरी प्रणाली में काम करने के तरीके बदल गये। इंजीनियर अधिक निर्णायक हो गए, ठेकेदार अधिक जवाबदेह बन गये तथा राज्य और केंद्रीय एजेंसियां अधिक निकटता से समन्वय करने लगीं, क्योंकि हिस्सों में काम करने को अब सहन नहीं किया जाता था। जमीनी स्तर पर, प्रभाव स्पष्ट था। सुरंग खुदाई पहले छिटपुट तरीके से की जा रही थी। जटिल भूविज्ञान, टूटे हुए चट्टान, संरचनात्मक बदलाव क्षेत्र, पानी का रिसाव और कमजोर स्तरों के बावजूद अब खुदाई के काम में लगातार प्रगति होने लगी। समर्थन प्रणालियों और डिजाइन संशोधनों के लिए अनुमोदन महीनों की बजाय हफ्तों में होने लगे। गहरी घाटियों में पुलों का नि

ाक ऊँचे थे, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर ि
और स्टील में बदल रहे थे। यहां तक कि को
निरंतरता सुनिश्चित करती रहीय श्रम की
चुनौतियों पर कड़ी निगरानी रखी गई, और
हुआ। समय के साथ, उपलब्धि का पैमाना
को कवर करने वाली पैंतालीस सुरंगें, 150
बिना बालास्ट वाला ट्रैक, और देश के सब
100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन ग
काउनपूई, मुअलखांग, और सैरांग लंबे सम
लिए तैयार हुए। इंजीनियरिंग से परे, परि
किया। नाजुक भूविज्ञान को प्रबंधित किया
हुए योजना बनाई जा सकती है और लॉजि
अंततः परिणामों को निर्धारित करने वाली चीज है शासन कृसंस्थाओं में समन्वय करने, निर्णय लेने और कार्रवाई करने की क्षमता।

पूर्वोत्तर में परियोजनाओं पर इसके प्रभाव से परे, प्रगति पोर्टल का देशव्यापी विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, क्योंकि निर्णय लेने में तेजी और बेहतर समन्वय ने पूरे देश में अवसंरचना के निरंतर विस्तार का समर्थन किया है। हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में, कैबिनेट सचिव ने प्रगति व्यवस्था के प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 तक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रगति व्यवस्था के तहत 382 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा कर चुके हैं। प्रगति इकोसिस्टम से 85 लाख करोड़ रुपये (लगभग 850 बिलियन डॉलर) से अधिक मूल्य की अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आयी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस अवधि के दौरान अवसंरचना परियोजनाओं के खर्च में भी तेज वृद्धि देखी गई है, जिसका पूंजीगत व्यय 2014–15 के 1.97 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025–26 में 11.21 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान तक पहुँच गया, जो पाँच गुनी से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। केन्द्रीय बजट में हिस्सेदारी के रूप में, अवसंरचना पूंजीगत व्यय लगभग 12 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 22 प्रतिशत हो गया। कैबिनेट सचिव के अनुसार दृ प्रगति एक व्यापक, एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में कार्य करती है, जिसमें पीएम गति शक्ति, परिवेश और परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) शामिल हैं।कुल मिलाकर देखा जाए तो, जमीन पर किए गए अवलोकन, स्थानिक परिणाम और वित्तीय संकेतक साथ मिलकर दर्शाते हैं कि भारत में अवसंरचना व्यय को व्यवस्थित रूप से बढ़ाया गया है और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया गया है, जिससे राष्ट्रीय विकास में एक स्थिर योगदानकर्ता के रूप में इसकी भूमिका मजबूत हुई है।

सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य पर नगर निगम का बड़ा कदम, वार्षिक मेडिकल जांच और कैंसर स्क्रीनिंग अनिवार्य

लखनऊ(संवाददाता)। शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत, सुरक्षित और मानवीय बनाने की दिशा में नगर निगम लखनऊ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत सभी सफाई श्रमिकों के लिए अब वार्षिक चिकित्सा परीक्षण और कैंसर स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा समस्त जोनल सेनेटरी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।निर्देशों के अनुसार नगर निगम के अधीन कार्यरत सभी नियमित, संविदा तथा कार्यदायी संस्थाओं के सफाई कर्मियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण और कैंसर स्क्रीनिंग एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। यह जांच निकटतम राजकीय चिकित्सालय में कराना सुनिश्चित किया जाएगा। नगर निगम का मानना है कि सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी से न केवल उनके जीवन की सुरक्षा होगी, बल्कि नगर की स्वच्छता व्यवस्था भी अधिक प्रभावी और सुदृढ़ हो सकेगी।नगर स्वास्थ्य अधिकारी पीके श्रीवास्तव ने बताया कि सफाई कर्मियों की यह चिकित्सा जांच निकटतम राजकीय चिकित्सालय, 108 अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा शहर के 8 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से किसी एक में कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य होगा और एक सप्ताह के भीतर इसकी सूचना संबंधित स्तर पर उपलब्ध करानी होगी।निर्देशों में यह भी कहा गया है कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत सभी कर्मियों की ओपीडी पर्ची, जांच रिपोर्ट, चिकित्सकीय परामर्श पत्र तथा अन्य संबंधित अभिलेख विधिवत संकलित किए जाएं और सुरक्षित रूप से रखे जाएं। इससे भविष्य में कर्मियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संधारित करने में भी सुविधा होगी।नगर निगम का यह कदम स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टिगत भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान से सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और वे अधिक सुरक्षित वातावरण में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। नगर निगम का यह निर्णय न केवल स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि सफाई कर्मियों के प्रति संवेदनशील प्रशासनिक सोच को भी दर्शाता है।

सोनू कश्यप हत्याकांड के विरोध में हजरतगंज में सपा का जोरदार प्रदर्शन, कार्यकर्ता हिरासत में, इको गार्डन भेजे गए

लखनऊ(संवाददाता)। मेरठ में सोनू कश्यप की नृशंस हत्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन किया और हत्याकांड के दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी तथा कड़ी कार्रवाई की मांग की। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध बेलगाम हो चुके हैं और आमजन, विशेषकर पिछड़े और कमजोर वर्ग, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें इको गार्डन भेज दिया। पुलिस कार्रवाई के बावजूद कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत नहीं हुआ और उन्होंने हिरासत के दौरान भी न्याय की मांग को दोहराया। इको गार्डन पहुंचने पर समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजपाल कश्यप ने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी।हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों में प्रमुख रूप से शिवम कश्यप, प्रदेश महासचिव समाजवादी युवजनसभा, एडवोकेट संदीप कश्यप, जिला अध्यक्ष समाजवादी युवजनसभा सीतापुर, राज साहनी, एडवोकेट जीतू कश्यप, एडवोकेट शिवम कश्यप, नीरज पाल, प्रदेश उपाध्यक्ष, हरनाम यादव हरदोई, अंकित यादव सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में सोनू कश्यप को न्याय दिलाने की मांग की।डॉ. राजपाल कश्यप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक सोनू कश्यप को न्याय नहीं मिलेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक समाजवादी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाएगी और प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था के सवाल पर जवाबदेह बनाएगी। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार उन्हें रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

हुसैनगंज में जानलेवा हमले के चार आरोपी गिरफ्तार, धारदार हथियार से युवक पर किया था हमला

लखनऊ(संवाददाता)। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के मध्य जोन अंतर्गत थाना हुसैनगंज पुलिस ने जान से मारने की नीयत से किए गए हमले के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने यह कार्रवाई थाना हुसैनगंज पर दर्ज मुकदमा संख्या 0002ध2026 के तहत की है, जिसमें आरोपियों पर एकराय होकर धारदार हथियार से हमला करने का गंभीर आरोप है।पुलिस के अनुसार यह मुकदमा 12 जनवरी 2026 को पुराना किला क्षेत्र निवासी नान बच्ची द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि नामजद अभियुक्तों ने एकजुट होकर वादिनी के पुत्र पर धारदार हथियार से हमला किया और उसकी हत्या करने का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।13 जनवरी 2026 को थाना हुसैनगंज पुलिस टीम ने अभियोग से संबंधित चारों आरोपियों सुहैल पुत्र रज्जब, समद पुत्र सुलेमान उर्फ पठान, अरमान पुत्र स्वर्गीय कल्लू और कृष्णा पुत्र स्वर्गीय रामदुलारे को एलिवेटेड रोड के किनारे से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त पुराना किला और आसपास के क्षेत्रों के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और उनके आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थानों और जनपदों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त अरमान का पूर्व आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ वर्ष 2020 में थाना हुसैनगंज में धारा 188 और 271 के तहत दो मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अन्य अभियुक्तों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।इस पूरी कार्रवाई में थाना हुसैनगंज के थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में कानून–व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

म्यूजिक टीचर को नान-टीचिंग स्टाफ मानते है निजी स्कूल

सीबीएसई बोर्ड के प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में हो रहा संगीत शिक्षकों का शोषण-विभाग मौन

लखनऊ,। राजधानी के प्रतिष्ठित विद्यालयों में शिक्षकों के शोषण के लिये निजी विद्यालय प्रबन्धन द्वारा नये–नये हथकंडे अपनाये जा रहे है। पी.जी.टी शिक्षक का निर्धारित वेतनमान न देना पड़े इस लिये संगीत अध्यापक को नान–टीचिंग स्टाफ बनाकर शिक्षक को नियुक्त करते है। ये खेला सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों में खुलआम चल रहा है। जिसमें राजधानी के प्रतिष्ठित व नामचीन विद्यालय शामिल है। इसमें शिक्षक का शोषण होता है। शिक्षा विभाग जो बाकी मामलों में सक्रिय रहता है परंतु हस तरह की घटनाओं पर निष्क्रिय रहता है। कक्षा दस के बाद बच्चें अपना टोटल परसेंट बढ़ाने के लिय संगीत विषय को लेते है। संगीत में प्रैक्टिल के सत्तर तथा थ्योरी के तीस अंक होते है। निजी विद्याालयों में प्रैक्टिल के पूरे अंक मिल हीजाते है संगीत में सौ में सौ मिलना काफी आसान होता है। जिससे टोटल परसेंट काफी अच्छा हो जाता है। वही एक म्यूजिक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता संगीत में विशारद् होती है तभी उसे सीनियर कक्षाओं में पढ़ाने के योग्य माना जाता है। संगीत पढ़ाने के लिये कोई पीरियड निर्धारित नहीं होता है। शिक्षक को जीरो पीरियड में पढ़ाना होता है। ताजा मामला राजधानी के प्रतिष्ठित लखनऊ पब्लिक कालेज का है जहां के विशारद् शिक्षक को इएटर के विद्याार्थियों को निर्धारित पीरियड में नहीं बल्कि जीरो पीरियड में संगीत की शिक्षा दिलवायी जा रही है। साथ ही नान–टीचिंग स्टाफ का वेतनमान दिया जा रहा है। शिक्षक मजबूरी में अपना शोषण करवाने को मजबूर है। शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिखा मंत्री आरटीई के प्रवेश के लिये निजी विद्यालयों पर निरन्तर दबाब बनाये रखते है परंतु विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक कैसे है क्या योग्यता है क्या वेतन मिल रहा है आदि की कोई जानकारी उनकों नहीं है। प्रतिवर्ष यू–डायस पोर्टल पर स्कूल, शिक्षकों, बच्चों व स्टाफ की सूचनायें मांग कर और उसे ही सही मानकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते है। संगीत विषय तो एक उदाहरण है। विभाग इमानदारी से देखें तो गली–गली में खुली स्कूली दुकानों में दस से बारह हजार में शिक्षक इण्टर के बच्चों को पढ़ा रहा है।

निवेश के नाम पर 1.92 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, फर्जी आधार-पैन से खाते खोलने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ(संवाददाता)। निवेश में अधिक मुनाफे का झांसा देकर करीब दो करोड़ रुपये की साइबर ठगी करने वाले शातिर अपराधी को साइबर क्राइम पुलिस थाना, कमिश्नरेट लखनऊ की टीम ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी पहचान बनाकर लोगों से संपर्क करता था और निवेश के नाम पर भारी रकम हड़प लेता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कूटरचित आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद किए हैं।साइबर क्राइम थाना लखनऊ के अनुसार 2 जून 2025 को पीड़ित शलभ पाण्डेय ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल नंबर पर एक महिला ने खुद को "भाविका शेट्टी" बताते हुए व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया। बातचीत और कॉल के माध्यम से मित्रता स्थापित करने के बाद आरोपी गिरोह ने निवेश कर अधिक लाभ कमाने का झांसा दिया और अलग–अलग बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 92 लाख 92 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए। बाद में यह पूरा मामला साइबर धोखाधड़ी का निकला। इस संबंध में थाना साइबर क्राइम लखनऊ में अपराध संख्या 87ध2025 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(डी) में मुकदमा दर्ज किया गया।मामले के अनावरण के लिए पुलिस आयुक्त लखनऊ के निर्देश पर साइबर क्राइम थाना लखनऊ में विशेष टीम का गठन किया गया। प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और बैंक लेन–देन के विश्लेषण के आधार पर मुख्य अभियुक्त इमरान गाजी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका एक्सिस बैंक खाता फ्रीज होने के बाद उसने फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाए और शहजाद नामक व्यक्ति के संपर्क में आकर विभिन्न बैंकों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए खाते खुलवाए। इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने और आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था।पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़ित से ठगे गए पैसों में से 54 लाख रुपये सीधे आरोपी के खाते में ट्रांसफर हुए थे। बैंक स्टेटमेंट के विश्लेषण में यह भी खुलासा हुआ कि महज एक महीने के भीतर आरोपी के खातों में करीब 1 करोड़ 52 लाख रुपये का संदिग्ध लेन–देन हुआ है। आरोपी द्वारा अपनाए गए तरीके में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फर्जी पहचान बनाकर संपर्क करना, निवेश में मोटे मुनाफे का लालच देना, फर्जी दस्तावेजों से खोले गए बैंक खातों का उपयोग करना और कमीशन पर रकम की निकासी कराना शामिल है।गिरफ्तार अभियुक्त इमरान गाजी निवासी मिश्रपुर डिपो, थाना गुड़म्बा, लखनऊ का रहने वाला है और उसकी उम्र 34 वर्ष बताई गई है। उसके खिलाफ इसी मामले में साइबर क्राइम थाना लखनऊ में आपराधिक इतिहास दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।साइबर क्राइम पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है,

मतदाता सूची में धांधली कर लोकतंत्र को अपवित्र करना चाहती है भाजपा, फर्जी वोट बनाने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर: अखिलेश यादव

लखनऊ(संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक बार फिर फर्जी वोट बनाने में जुटी हुई है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपवित्र करने पर उतारू है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि वोट बनाने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की हेराफेरी की गई तो फर्जी वोट बनवाने वालों के साथ–साथ इसमें शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि एफआईआर का प्रारूप समाजवादी पार्टी के सभी बीएलए और बूथ प्रभारियों को भेजा जा रहा है।मंगलवार को समाजवादी पार्टी राज्य मुख्यालय, लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर घर–घर जाएं और जनता से सीधे संवाद स्थापित करें। उन्होंने कहा कि लोगों को समाजवादी पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और जनहितकारी सोच से अवगत कराना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने प्रदेश की जनता से भाजपा की साजिशों के प्रति सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश का मतदाता भाजपा के साथ नहीं है।अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा भूमाफिया की भूमिका में आ गई है। प्रदेश भर में सरकारी जमीनों और गरीबों की जमीनों पर भाजपाई नेताओं द्वारा अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और लूट अपने चरम पर है और ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है, जहां भ्रष्टाचार न हो। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का नामोनिशान मिट जाएगा।मतदाता सूची के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया ही वास्तव में एनआरसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो काम गृह मंत्रालय का था, उसे भाजपा सरकार चुनाव आयोग से करा रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद भी मतदाता सूची में लगातार खामियां सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि चार करोड़ वोट काटे जा रहे हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में भारी अंतर है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता सूची में 12 करोड़ 56 लाख मतदाता हैं, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही 12 करोड़ 69 लाख मतदाता दर्शाए गए हैं। यदि इसमें शहरी मतदाताओं की संख्या जोड़ दी जाए तो कुल मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ से अधिक हो जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मतदाता सूची तैयार करने वाले बीएलओ और अधिकारी–कर्मचारी वही हैं, तो फिर मतदाताओं की संख्या के आंकड़े अलग–अलग कैसे हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह अंतर भाजपा की नीयत और मतदाता सूची में हेराफेरी की साजिश को उजागर करता है और समाजवादी पार्टी इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी।

शाइनिंग स्टार्स ने मनाया अपना पन्द्रहवां स्थापना दिवस

लखनऊ,। राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने तथा फशर युवाओं व अनुभवी लोगों को रोजगर के अवसर उपलब्ध वाली प्रसिद्ध शाइनिंग स्टार्स कंपनी ने अपना पन्द्रहवा स्थापना दिवस काफी धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम जिद्दी थीम पर मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक बिल्हौर–कानपुर राहुल बच्चा सोनकर उपस्थित थे। साथ ही विशिष्ठ अतिथ के रूप में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की सदस्य सबीहा अहमद, मुख्य मंत्री के मीडिया सलाहकार डा0 रहीस अहमद भी उपस्थित थे। शाइनिंग स्टार्स के वाईस प्रेजिडेंट देव चिन्मय ने बताया कि कोरोना काल में कंपनी ने बेरोजगारों के लिए उत्कृष्ट कार्य किया था। तथा उस दौर में आठ हतार से अधिक लोगों को राजगाा उपलब्ध कराया था। अपने पद्रहवें स्थापना दिवस तक शाइनिंग स्टार एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा चुकी है। ज्ञात हो कि शाइनिंग स्टार्स देश के विभिन्न कॉर्पोरेट कंपनियों को मानव संसाधन की सेवा प्रदान करती है। कंपनी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यह सेवा नौकरी ढूंढ रहे युवक–युवतियों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस अवसर पर विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने कहा कि रोजगार सृजन व रोजगर उपलब्ध कराने की दिशा में शाइनिंग स्टार की भूमिका काफी सराहनीय है। उन्होाने उ0प्र0 के मुख्यमंत्री के कौशल विकास व युवाओं को रोजगार प्रदान करने संबधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की। सभीहा अहमद ने कहा कि शाइनिंग स्टार में अस्सी प्रतिशत कर्मचारी मातृ शक्ति है जो महिला सशक्तीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस अवसर पर उत्कृष्ट सेवा एवं प्रदर्शन के लिए टॉप परफार्मर को सम्मानित किया गया। जिसमें वंशिका जायसवाल को बेस्ट परफॉमसर ऑफ द ईयर, होमा फ़ैजारी को बेस्ट टीम लीडर, श्रद्धा देशपाण्डे को बेस्ट मैनेजर के पुरस्कार से मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ टीम लीडर किरण यादव ने कहा कि कंपनी द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुये दो सौ वंचित बच्चों को स्कूली बैग वितरित यि गये। कंपनी भविष्य में अर्न्तराष्ट्रीय सेवायें प्रदान करने की योजना बना रही है। जिद्दी थीम पर मनाये गये पद्रहवें स्थापना दिवस का संचालन अली मुस्तफा व पलाक्षी ने किया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आये स्टार्टअप फाउन्डर्स व विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

मकर संक्रांति स्नान पर्व के लिए तैयारी पूरी

लखनऊ)। प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व मकर संक्राति 15 जनवरी को है। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व में 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को सकुशल स्नान संपन्न कराने के बाद अब मेला प्रशासन ने मकर संक्रांति स्नान पर्व के लिए कमर कस ली है। स्नान घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, इसके लिए घाटों के समीप ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस दौरान एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का प्रशासन का अनुमान है।माघ मेला 2024 में इस पर्व पर 28.95 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। इस बार तीन गुना अधिक श्रद्धालुओं के आगमन के अनुमान को देखते हुए मेला प्रशासन ने भी भीड़ प्रबंधन का मेगा प्लान तैयार किया है। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज का कहना है भीड़ प्रबन्धन एवं सुगम यातायात के दृष्टिगत 42 अस्थायी पार्किंग विकसित की गयी है, एक लाख से अधिक वाहन पार्क हो सकेंगे। माघ मेला 2025–26 में 12100 फीट लम्बाई में घाटों का निर्माण किया गया है जिनमे मूलभूत सुविधाएं चेंजिंग रूम, पुऑल, कॉसा, शौचालय आदि उपलब्ध हैं। माघ मेले में गंगा में जल की उपलब्धता के लिए कानपुर के गंगा बैराज से प्रतिदिन 8000 क्यूसेक जल छोड़ा जा रहा है। प्रयागराज में दोनों नदियों में गिरने वाले 81 नालों की टैपिंग की जा चुकी है। निरंतर गंगा जल की मॉनिटरिंग हो रही है।माघ मेले में स्वच्छता, सुरक्षा और सुगम परिवहन पर विशेष जोर दिया गया है। मेला अधिकारी ऋषिराज बताते हैं कि माघ मेले को खुले में शौच मुक्त, दुर्गन्ध मुक्त और गंगा में जीरो डिस्चार्ज हेतु 25,880 शौचालय, 11 हजार डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 25 सक्शन गाड़ियां एवं 3,300 सफाई कर्मी तैनात किये गये हैं। श्रद्धालुओं के सुगम एवं सुलभ आवागमन हेतु बाइक टैक्सी और गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गयी है। माघ मेला पुलिस अधीक्षक नीरज पांडेय बताते हैं कि मेला क्षेत्र में 17 थाने व 42 पुलिस चौकी, 20 अग्निशमन स्टेशन, 7 अग्निशमन चौकी, 20 अग्निशमन वॉच टावर, 1 जल पुलिस थाना, 1 जल पुलिस कन्ट्रोल रूम तथा 4 जल पुलिस सब कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। 8 किलोमीटर से अधिक डीप वाटर बैरीकेडिंग एवं 2 किलोमीटर रिवर लाइन एकल दिशा मार्ग हेतु लगायी गयी है। पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गयी है। नगर एवं मेला क्षेत्र में पूर्व से स्थापित सीसीटीवी कैमरों के अतिरिक्त एआई युक्त कैमरों सहित 400 से अधिक कैमरों के माध्यम से क्राउड मानिटरिंग, क्राउड डेन्सिटी एनालिसिस, इन्सीडेन्ट रिपोर्टिंग, स्वच्छता एवं सुरक्षा निगरानी की व्यवस्था की गयी है।

मनरेगा थी लूट की गारंटी, जी राम जी में भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं : रिजिजू

लखनऊ। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जनता से नरेन्द्र मोदी सरकार की विकसित भारत–जी राम जी योजना को लेकर हो रहे दुष्प्रचार के प्रभाव में नहीं आने का आह्वान करते हुए कहा कि लूट की गारंटी वाले मनरेगा के विपरीत जी राम जी कानून में एक रुपये का भी भ्रष्टाचार होने की गुंजाइश नहीं है। रिजिजू ने विकसित भारत–जी राम जी योजना को लेकर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आयोजित कार्यशाला के बाद प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) में दरअसल लूट की गारंटी थी। उन्होंने दावा किया कि उसमें ऐसी व्यवस्था की गयी थी जिसमें कुछ लोग तिकड़म करके करोड़ों रुपये लूट लेते थे। मंत्री ने विपक्ष द्वारा मनरेगा को खत्म करके विकसित भारत–जी राम जी योजना शुरू किये जाने का विरोध करने का जिक्र करते हुए कहा, दुष्प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। जब संशोधित नागरिकता कानून लाया गया था, तब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों ने दुष्प्रचार करके देश भर में मुसलमान को बरगलाने का काम किया कि नागरिकता कानून पारित होने से सारे मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऐसा झूठ फैलाकर गुमराह करने की कोशिश की गयी। जब यह कानून पारित हुआ तो बताइए कि क्या किसी मुसलमान की नागरिकता छीनी गई। विकसित भारत–जी राम जी को लेकर भी ऐसा ही कुछ प्रचार करने की कोशिश की जाएगी। मगर जी राम जी अब कानून बन चुका है और इसे लागू करने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बदलाव भी आपको जल्द ही दिखाई देगा। उन्होंने मनरेगा खत्म करके महात्मा गांधी का नाम हटाने की साजिश के आरोप सम्बन्धी एक सवाल पर कहा, मनरेगा के नाम के पीछे क्यों पड़े हैं? जो भ्रष्टाचार का साधन था, उस पर हम क्यों बात करें? हमको काम देखना है, नाम नहीं। पुराना कानून ऐसा था कि जिसमें भ्रष्टाचार रोका ही नहीं जा सकता था। रिजिजू ने कहा कि नये कानून में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है और सारी व्यवस्था डिजिटल की गयी है। उन्होंने कहा कि 'जोन मैपिंग और सैटेलाइट मैपिंग' करके विकसित भारत–जी राम जी की हर परियोजना की नीचे से लेकर ऊपर तक निर्धारित मापदंडों के अनुरूप लगातार निगरानी की जाएगी और एक रुपये की भी धांधली नहीं हो सकेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा में 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च होने के बावजूद ग्रामीण इलाकों का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। रीजीजू के मुताबिक, इसके अलावा, मनरेगा के माध्यम से जिस राज्य को जितनी धनराशि की जरूरत होती थी, उतनी नहीं मिल पाती थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नये कानून में 100 दिन की रोजगार गारंटी की अवधि को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही अगर इसमें किसी तरीके से विलंब होता है तो उसका हर्जाना वसूले जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी योजना इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे ज्यादा आबादी और सर्वाधिक गांव उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिये ज्यादा बदलाव भी उत्तर प्रदेश में ही होने वाला है।

हम गांधीजी के नहीं, उनके नाम पर लूट वाली कांग्रेसी योजनाओं के विरोधी- केशव

वीबी जीराम जी राष्ट्र निर्माण, चेतना, समरसता, जनभागीदारी का माध्यम

लखनऊ,। केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू की अध्यक्षता में विकसित भारत जी राम जी जनजागरण अभियान के कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और खुलकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता, सुशासन, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।श्री मौर्य ने वीबी जीराम जी के मूल भाव को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह अभियान राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता, जनभागीदारी को मजबूत करने का माध्यम है।उन्होनें कहा कि मनरेगा 2006 में प्रारंभ हुई।हम महात्मा गांधी जी के विरोधी नहीं, उनके नाम पर लूट करने वाली कांग्रेस की योजनाओं के विरोधी हैं।मनरेगा में 11 लाख करोड़ गड़क गए और विकास नहीं हुआ, हम इसके विरोधी हैं।विकसित भारत, विकसित गॉव की परिकल्पना से प्रेरित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी राम जी 2025 कानून को देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पारित कराकर राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कानून गरीब, वंचित और श्रमजीवी वर्ग के कल्याण, सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने कहा,गरीब को 100 दिन के स्थान पर 125 का कार्य मिले इसमें क्या गलत है। गरीब के मजदूरी का भुगतान 60 दिन में गारंटी से हो इसमें कांग्रेस को दर्द क्यों।डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पैसा जाए इसमें क्या गलत है। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, जीआईएस आधारित मोबाइल एप तथा फेस रीडिंग जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। गॉव में रोजगार मिलने से पलायन रुकेगा, गॉव का विकास होगा। रामराज्य की अवधारणा, न्याय, सेवा, समानता और सुशासन आज की नीतियों में साकार हो रही है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, आवास, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने जनजागरण अभियान के माध्यम से सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का आह्वान किया।इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय राज्य मंत्री व भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राज्य सभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा उत्तर प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धानखाड़ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह सूर्य प्रताप शाही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह एवं भाजपा उत्तर प्रदेश के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी उपस्थिति रहे।

छात्राओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम, समाज कल्याण विभाग व मदद फाउंडेशन के बीच एमओयू

लखनऊ।छात्राओं के समावेशी विकास, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसी क्रम में मंगलवार को गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में मदद फाउंडेशन के सहयोग से समन्वय बैठक एवं टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग और मदद फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री असीम अरुण तथा मदद फाउंडेशन के संस्थापक श्री राजेश मणि उपस्थित रहे।

हर बालिका विद्यालय को 20–20 टैबलेट

कार्यक्रम के दौरान जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय, गोरखपुर एवं महराजगंज जनपदों के प्रधानाचार्यों को कुल 40 टैबलेट प्रदान किए गए। ये टैबलेट संबंधित विद्यालयों की छात्राओं के शैक्षणिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय को 20–20 टैबलेट दिए गए हैं। यह पहल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है, जिसकी सफलता के आधार पर भविष्य में अन्य विद्यालयों को भी टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की योजना है।

'डिजिटल शिक्षा समय की अनिवार्य आवश्यकता'

इस अवसर पर टैबलेट वितरित करते हुए राज्य मंत्री श्री असीम अरुण ने कहा कि डिजिटल शिक्षा आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। तकनीकी संसाधनों के माध्यम से छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ–साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने इस पहल को बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय एवं दूरदर्शी कदम बताया।

'शिक्षा के क्षेत्र में एक सार्थक प्रयास'

मदद फाउंडेशन के संस्थापक श्री राजेश मणि ने समाज कल्याण विभाग के साथ इस सहयोग को सामाजिक उत्थान और शिक्षा के क्षेत्र में एक सार्थक प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों के माध्यम से छात्राओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सकेगा।

कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के निदेशक श्री संजीव सिंह, उपनिदेशक श्री आनंद कुमार सिंह, श्री जे. राम सहित विभागीय अधिकारी एवं मदद फाउंडेशन की टीम के सदस्य उपस्थित रहे।

माघ मेला 2026: संगम तट पर आधुनिक टेंट सिटी, आस्था के साथ पर्यटन और रोजगार को नया आयाम

लखनऊ।।मकर संक्रांति सहित अन्य प्रमुख स्नान पर्वों पर प्रयागराज संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त टेंट सिटी विकसित की गई है। संगम की पुण्य धारा में स्नान के लिए देश–विदेश से श्रद्धालुओं का निरंतर आगमन हो रहा है। इसी क्रम में सुरक्षित, सुविधाजनक और यादगार अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने संगम तट की रेत पर अत्याधुनिक टेंट कॉलोनी बसाई है, जो कल्पवासियों और पर्यटकों के लिए आस्था के साथ–साथ आकर्षण का नया केंद्र बनकर उभरी है। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी।उन्होंने बताया कि प्रयागराज के अरैल सेक्टर–7 में त्रिवेणी पुष्प से पहले विकसित इस टेंट कॉलोनी में कुल 50 आधुनिक कॉटेज बनाए गए हैं। इनकी ऑनलाइन बुकिंग यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। टेंट कॉलोनी को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया हैकृ 15,000 रुपये किराए वाला प्रीमियम, 11,500 रुपये का लग्जरी और 7,500 रुपये का डीलक्स कॉटेज। इनमें 12 प्रीमियम, 8 लग्जरी और 30 डीलक्स टेंट शामिल हैं। सभी श्रेणियों में ठहरने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुल्क में ही सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है।टेंट कॉलोनी परिसर में यज्ञशालाओं का निर्माण किया गया है, जहां निरंतर भजन–कीर्तन हो रहा है। सांस्कृतिक वातावरण को सजीव बनाने के लिए कलाग्राम भी विकसित किया गया है, जहां स्थानीय शिल्प और लोककला को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।पर्यटन मंत्री ने बताया कि माघ मेले के माध्यम से रोजगार और नवाचार को भी विशेष बढ़ावा मिला है। संगम टेंट कॉलोनी में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) प्रदर्शनी के तहत प्रयागराज की पारंपरिक मूंज कला के स्टॉल लगाए गए हैं जिससे स्थानीय कारीगरों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। माघ मेला 2026 न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त कर रहा है, बल्कि उद्यमियों और हस्तशिल्पियों के लिए भी एक बड़ा व्यावसायिक मंच बनकर उभरा है। यहां देश–विदेश से आए श्रद्धालु मूंज से बने डलिया, पेन स्टैंड, रोटी रखने के बर्तन, गमले और सजावटी वस्तुओं को खूब पसंद कर रहे हैं।

नैनी क्षेत्र के महेवा इलाके की यह पारंपरिक मूंज कला, जिसे चांद जैसी कारीगर वर्षों से आगे बढ़ा रही हैं, अब आधुनिक स्वरूप में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना पा रही है।जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप माघ मेला अब केवल आस्था का आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि यह पर्यटन, रोजगार और स्थानीय कला को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम बन चुका है। यूपीएसटीडीसी द्वारा विकसित संगम टेंट कॉलोनी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ओडीओपी योजना के तहत मूंज कला जैसे पारंपरिक शिल्प को मंच देकर स्थानीय कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश का हर आयोजन रोजगार, नवाचार और संस्कृति से जुड़े, और माघ मेला 2026 इस सोच को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है।

मोटर साइकिल वाहनों के विरुद्ध की कार्यवाही

(सुनील शर्मा)

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में उतर प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। उक्त के क्रम में सड़क सुरक्षा माह के तेरहवें दिन सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को ध्यान रखते हुए परिवहन विभाग लखीमपुर खीरी द्वारा बिना हेलमेट मोटरसाइकिल संचालित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए 105 के विरुद्ध चलान की कार्यवाही की गई तथा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया प्रवर्तन कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए ए0आर0टी0ओ0 द्वारा ओवरलोडिंग एवं ओवरहाइट वाहनों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई तथा पीटीओ डॉ कौशलेंद्र द्वारा क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के साथ साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 4 वाहनों को निरुद्ध किया गया

तत्त्वज्ञान प्राप्त महात्माओं की वाणी गूंजेगी प्रयागराज में

धर्म क्षेत्र भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं - महात्मा दशरथ जी

(केके शुक्ला)

लखीमपुरध्प्रयागराज। स्वामी सदानन्द जी परमहंस द्वारा संस्थापित संस्था सदानन्द तत्त्वज्ञान परिषद् के तत्त्वावधान में माघ मेला महावीर चौराहा समीप सेक्टर 2, प्लॉट नं 2, अपर संगम मार्ग के शिविर में अदभुत सत्संग एवं भजन कीर्तन का कार्यक्रम 14 जनवरी से शुभारंभ होने जा रहा है । कार्यक्रम में भगवान विष्णु जी, राम जी एवं कृष्ण जी का तत्त्वज्ञान एवं सच्चा धर्म के विषय में जनसमाज को बताया जाएगा। कार्यक्रम के लिए उपस्थित महात्मा कमल जी ने कहा कि वास्तव में दोष रहित, सत्य प्रधान , उन्मुक्त अमर जीवन पद्धति ही धर्म है, धर्म वह विधान का नाम है जिससे हमें बार बार के जनम–मरण के चक्कर से, इस भव सागर से छुटकारा मिल जाता है । अत रू जनसमाज को चाहिए कि सच्चा धर्म को जानकर उसके विधान में अपने को रखकर रहें चलें। महात्मा दशरथ जी ने कहा कि कलियुग के प्रभाव से धर्म दूषित हो चुका है , क्योंकि जिस तरह आज समाज में भ्रष्टाचार चरम में है उसी तरह धर्म क्षेत्र भी आज भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है । इसका प्रमुख कारण यही है कि आज जनसमाज धर्म की वास्तविक जानकारी से विमुख हो गया । परमेश्वर की वास्तविक जानकारी से विमुख हो गया । भगवान को जानना तो बहुत दूर, वह आत्मा और जीव को भी नहीं जानता । ऐसे जीव को भी न जानने वाले मिथ्या महत्वाकांक्षी लोग गुरु, सदगुरु और भगवान बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं । जिससे समाज में धर्म अनेकों संप्रदाय में बंट गया है जिसके कारण आपसी टकराव बढ़ रहा है । उन्होंने कहा मेरे सदगुरु देव सन्त ज्ञानेश्वर स्वामी सदानन्द जी परमहंस ने श्रीविष्णु जी श्रीराम जी श्रीकृष्ण जी वाला ही तत्त्वज्ञान दे कर जीव आत्मा और परमात्मा तीनों का अलग अलग साक्षात् दर्शन कराया है । आज सदानन्द तत्त्वज्ञान परिषद् के भक्त सेवक धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा कार्य में पूर्णतया समर्पित हैं।26 जनवरी के दिन प्रातःकाल धर्म धर्मात्मा धरती रक्षार्थ सत्य धर्म संस्थापनार्थ विशाल भगवद शोभायात्रा माघमेला परिसर में निकाली जाएगी और 15 जनवरी से प्रातःकालीन समय में श्रीराम कथा एवं श्रीमद्भगवद् कथा भी होगा।

राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित

लखीमपुर–खीरी, 13 जनवरीरू युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत लखीमपुर व जिला युवा अधिकारी संकल्प शुक्ला के मार्गदर्शन में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के तहत मैथमैटिकल स्टडी प्वाइंट कोचिंग सेंटर में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता व संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश कुमार कोचिंग संचालक रहे।

प्रतियोगिता में 50 से अधिक संख्या में विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित करते हुए प्रथम स्थान जितिन वर्मा, द्वितीय स्थान योगेन्द्र सिंह तथा तृतीय स्थान समर मौर्य ने प्राप्त किया। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।मुख्य अतिथि राजेश कुमार ने विजेता छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं। कार्यक्रम का संचालन रितेश वर्मा युवा मण्डल अध्यक्ष द्वारा किया गया तथा समापन प्रेरक संदेश के साथ किया गया

क्या शिकायतकर्ता की दौड़ बंद होने के इंतजार में है सहकारिता विभाग

समिति की जमीन पर कौन कर रहा है खेती?

(हरिशंकर मिश्रध्सत्यदेव)

लखीमपुर खीरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का दावा कर रहे हो परंतु जिले का सहकारिता विभाग उनके इस दावे को पूर्णतया झुठलाने पर तुला हुआ है। मामला सदर तहसील के ब्लॉक फूलबेहड़ स्थित चभाल कृषि सहकारी समिति बसैगापुर की 258 एकड़ जमीन पर काबिज भूमाफिआयों को लेकर चर्चा में काफी समय से बना हुआ है। इस समिति के पूर्व सचिव सरदूल सिंह के कई वर्षों के प्रयासों के बाद गत वर्ष 4 अप्रैल 2025 को गेहूं की फसल को भूमाफियों द्वारा काटने व उस जमीन पर जाने से रोक लगाई थी किसी आदेश को निरस्त करने के लिए भू माफिया चंद्रप्रकाश व अन्य मा0 उच्च न्यायालय तक गए लेकिन उच्च न्यायालय ने ओ माफियाओं की रिट को खारिज कर दिया अर्थात प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक को वैध माना। मामले में फैली जन चर्चाओं के अनुसार लोगों का मानना है कि इसके बाद भू माफियाओं ने सहकारिता विभाग के अफसरों से सांठ गांठ करके गेहूं काट लिया और कुछ दिन तक सहकारी समिति की यह जमीन खाली पड़ी रही फिर भू माफियाओं ने सहकारिता विभाग के अफसर से सांठ गांठ करके धान लगाकर उसकी फसल भी काट ली और पुनः उसमें गेहूं की फसल बोकर सिद्ध कर दिया कि भू माफिया बाहुबली होते हैं जिनके सामने किसी प्रकार का सारा बल बौना होता है। भूमाफियाओं का कहना है कि वह रोक के बाद जमीन के पास नहीं गए हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठता है की जमीन आखिर कौन जोत बो रहा है? मामले में सहकारिता विभाग के जिला सहायक निबंधक रजनीश प्रताप सिंह से जानकारी लेने पर अपने सुर बदलते हुए कहने लगे हैं कि एसडीएम सदर भी इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं जांच रिपोर्ट आने के बाद अपनी विभागीय रिपोर्ट व एसडीएम की रिपोर्ट टैली करने के बाद निर्णय लेंगे। जैसा कि उनके कथन से ही स्पष्ट है की वह माफियाओं की एक तरह से मदद ही कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले के शिकायतकर्ता सरदूल सिंह जो 80 साल के हो रहे हैं आखिर कब तक जिएंगे और चक्कर लगा पाएंगे। दूसरी तरफ मामले में उभर रहे अन्य माफियाओं जिनके द्वारा एक अन्य समिति फर्जी तरीके से बनाकर बैंक खाता चालू कराने में भी अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे उनके भी हौसलों में भी कोई कमी नहीं आई।बताया जाता है की समिति की इस विवादित जमीन पर एक विद्यालय भी भूमाफियाओं द्वारा चलाए जा रहा है जिसकी मान्यता बेसिक शिक्षा विभाग ने लगभग 8 साल पूर्व दी थी।

मेट्रो कारिडोर के पास पतंग उड़ाने से बचें, चीनी मांझा जानलेवा : लखनऊ मेट्रो

लखनऊ।यात्रियों की सुरक्षा और मेट्रो सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लखनऊ मेट्रो ने आमजन से अपील की है कि वे मेट्रो कॉरिडोर के आसपास पतंग उड़ाने से परहेज करें। पूर्व में पतंगबाजी के कारण मेट्रो परिचालन प्रभावित हुआ है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

लखनऊ मेट्रो ने बताया कि चीनी मांझा अथवा धातुयुक्त धागा विद्युत का सुचालक होता है। इसके संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे जान–माल की हानि की आशंका रहती है। साथ ही इससे मेट्रो की ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (ब्म्) प्रणाली को भी गंभीर क्षति पहुंच सकती है।

धातुयुक्त धागा यदि ओएचई सिस्टम में फंसता है तो ट्रिपिंग की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप मेट्रो सेवाएं बाधित हो जाती हैं। ऐसे मामलों में पतंग उड़ाने वाले व्यक्तियों के घायल होने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।

लखनऊ मेट्रो ने स्पष्ट किया कि प्रचलित नियमों के तहत मेट्रो संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 की धारा 78 के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तारी और 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

लखनऊ मेट्रो ने नागरिकों से अपील की है कि वे चीनी मांझा अथवा तांबे के तार का प्रयोग न करें तथा मेट्रो कॉरिडोर के निकट पतंग उड़ाने से बचें, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और मेट्रो सेवाओं का निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

अंत में लखनऊ मेट्रो ने समस्त नागरिकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं।

लेखपाल द्वारा गई की जांच में अवैध कब्जा की पुष्टि, फिर भी कार्रवाई शून्य

नित्यानंद बाजपेईध्हरिशंकर मिश्र

लखीमपुर खीरी। जनपद में बच्चों की खेल शिक्षा और स्वास्थ्य तथा बच्चों के हकों पर डाका डालने वाला एक सनसनीखेज ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसे सुनकर आपके पैरों के ताले की जमीन खिसक जाएगी। विकास के नाम पर विनाश के सौदागरों ने चंद कागज के टुकड़ों की खातिर दबंग भू माफियाओं से साठ गांठ करके दशकों वर्ष पुराने और राजस्व अभिलेखों में दर्ज खेल मैदान को दफन करना शुरू कर दिया गया। और इसकी रक्षा को नियुक्त लोक सेवक स्वयं भक्षक की भूमिका में नजर आते हुए वह भू माफिया के ताल पर थिरकते देखे जा रहे हैं।

साजिश की गहराईरू कौन है इस खेल मैदान और प्राइमरी पाठशाला भूमि की तबाही का मास्टरमाइंड ऋ

खबर मिली है कि ग्राम पंचायत जटपुरा में खेल मैदान और प्राइमरी पाठशाला की आरक्षित, जमीन के साथ साथ खलिहान, हरिजन बस्ती की आरक्षित सरकारी जमीनों पर कई राशूखदार दबंग किस्म लोगो ने प्रधान, लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक से मिलीभगत करके ग्राम पंचायत की रिक्त पड़ी सरकारी जमीनों तथा खेल मैदान का गला घोंटने या यूं कहे वजूद मिटाने की सुपारी ले रखी है। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी सरकारी परमिशन और बगैर बिना किसी भाई के खुले आम अवैध कब्जा करके आलीशान मकान और दुकान खड़ी कर ली गई मौके पर जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो वहां मौजूद अवैध कबजेदारों द्वारा दादागिरी दिखाई जाने के आप भी लगाए जा रहे हैं लेकिन उक्त अवैध कब्जा धारकों के पास दिखाने के लिए एक कागज का टुकड़ा तक नहीं है।

बच्चों की खेल शिक्षा पर मंडराया खतराऋ

यहां पर सिर्फ सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला नहीं बल्कि बच्चों के खेल के मैदान पर अवैध कब्जा कर बिल्डिंग बनाएं जाने का मामला है जो बच्चों के भविष्य को संवारने और खेल के प्रतिभा निखारने वाला स्थान और बच्चों के भविष्य का मैदान है। यदि यह खेल मैदान नष्ट हो गया तो हजारों बच्चों की खेल प्रतिभाओं का गला घुट जाएगा और सरकार की मंशा पर भी पानी फिर जाएगा।

प्रशासन को सीधी चुनौतीरूऋआखिर कब जागेगा कुंभकर्णी नीद में सोया सिस्टम?

ग्रामीण और समाजसेवी लोगों में राजेंद्र कुमार ने इस असम में अपराध के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और मुख्यमंत्री सहित शासन प्रशासन को शिकायती पत्र देकर पूछा है क्या दबंग और रसूखदारों को कानून से ऊपर रहने और खेल मैदान ,प्राइमरी पाठशाला के नाम दर्ज कागजात सरकारी भूमि पर कब्जा करने की खुली छूट मिली हुई है?जनता पूछ रही है ऋआखिर किसकी सह पर खेल मैदान और प्राइमरी पाठशाला की आरक्षित देश कीमती जमीन पर बनाए जा रहे मकान और दुकान?

ऐसी क्या मजबूरी है जो खेल मैदान और प्राइमरी पाठशाला के आरक्षित जमीन पर किए गए पक्के निर्माण का ध्वस्थिकरण नहीं किया जा रहा है? क्या प्रशासन ने अवैध कबजेदारों के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या योगी सरकार खेल मैदान का वजूद मिटाए जाने का तमाशा देखती रहेगी। उपरोक्त मामले में ग्रामीण और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि यदि खेल मैदान से अवैध कब्जा न हटाया गया और खेल मैदान तथा प्राइमरी पाठशाला के नाम दर्ज कागजात जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले दोषी लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो यह मामला कागजों तक ही सीमित नहीं रहेगा जन आंदोलन की आज मुख्यालय तक पहुंचेगी और साथी उच्च न्यायालय का चलेगा कई जिम्मेदार अफसर पर कानूनी हंटर। अब देखना यह है ऊंट किस करवट बैठता है खेल मैदान और प्राइमरी पाठशाला के नाम दर्ज जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया जाता है या फिर यूं ही पूर्व की भाती लीपापोती कर मामले को फाइलों में दफन कर दिया जाएगा।

पंजीकृत पात्र आवेदकों के शीघ्र बनेंगे राशनकार्ड- विजय शुक्ला रिंकू।

337 लोगों ने कराया पंजीकरण,

गोलागोकर्णनाथ । मंगलवार 13 जनवरी खुटार रोड स्थित फूलबाबा आश्रम के पास नगर पालिका परिषद गोला के तत्वावधान में कैम्प के छठवें दिवस कुल 337 रजिस्ट्रेशन हुए। खुटार रोड लाम्बा स्थित फूलबाबा आश्रम के पास विभिन्न समस्याओं को लेकर लोगों नें रजिस्ट्रेशन कराए जिसमें वृद्धावस्था के43 रजिस्ट्रेशन हुए जिसमें 37 लोगों की पेंशन रुकी हुई थी 06 नये रजिस्ट्रेशन किए गए ,राशनकार्ड के 200 लोगों ने कैम्प में पंजीकरण कराया जिसमें 168 कार्डधारक थें जिनको यूनिट बढवानी थी शेष 32 नये कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन हुए ,विद्युत विभाग के 08 पंजीकरण हुए 03 स्मार्ट मीटर की रीडिंग के रजिस्ट्रेशन थे तथा 05 बिल बढोत्तरी के लिए पंजीकरण हुए,दिव्यांग पेंशन के 04,विधवा पेंशन के 14 पंजीकरण हुए। नगर पालिका परिषद से सम्बंधित 32 पंजीकरण हुए जो जन्मप्रमाण के थे ।साथ ही नये मतदाता बनने के भी 30 फार्म वितरित किए गए ।नगर पालिका आपके द्वार अभियान में उपस्थित आमजन को सम्बोधित करते हुए पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने कहा कि,ष पंजीकृत पात्र आवेदकों के शीघ्र राशनकार्ड बनेंगे तथा यूनिट बढाने का काम भी होगा ।बसपा नेता सभासद इजरान ने कहा,ष चेयरमैन साहब का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है ।15जनवरी को त्रिलोक गिरि में होने वाला कैम्प 16 जनवरी को नगर पालिका परिषद में प्रातरू 10 बजे से 04 बजे तक कैम्प रहेगा ।इस अवसर पर सभासद इजरान ,राजेश वर्मा,नगर पालिका से लेखाकार मोहित अवस्थी, जेई अनिल कुमार यादव, जेई आदर्श मिश्रा, श्रवण कुमार मिश्रा, अंकित गुप्ता,अशोक मिश्रा,विजय कुमार, प्रदीप कुमार,अनुज अवस्थी,विमलेश वर्मा,जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से विकास वर्मा , जिला समाज कल्याण विभाग अंकित सिंह,खाद्य एवं रसद विभाग से अजय कुमार,आनंद कुमार ,प्रोवेशन कार्यालय लखीमपुर से रामकुमार वर्मा, भाजपा से कैलाश गुप्ता, मनोज गुप्ता,राकेश शर्मा, हर्ष कटियार, राजेश राठौर, शत्रोहन मिश्रा आदि मौजूद रहे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का अवकाश, 14 जनवरी को रहेगा कार्यदिवस

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ खंडपीठ में 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को मकर संक्रांति के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना के क्रम में लिया गया है।हालांकि, इसके स्थान पर 14 जनवरी 2026 (बुधवार) को इलाहाबाद हाईकोर्ट तथा लखनऊ खंडपीठ में सामान्य रूप से न्यायिक कार्य होंगे। यानी 14 जनवरी को अदालतें खुली रहेंगी और सभी न्यायिक व प्रशासनिक कार्य पूर्ववत संपन्न किए जाएंगे।

हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह व्यवस्था इलाहाबाद मुख्य पीठ और लखनऊ खंडपीठकृदोनों पर समान रूप से लागू होगी।

पुलिस चौकी इमारत अति जीर्ण-शीर्ण व जर्जर

गोला गोकर्णनाथ खीरी। थाना नीमगांव की पुलिस चौकी सिकंदराबाद जो कि अति जीर्ण–शीर्ण व जर्जर हो गई है, वह कभी भी भरभरा के गिर सकती है जिससे कभी भी किसी बड़ी घटना होने से इन्कार नही किया जा सकता है।

ज्ञात हो कि लगभग पैतिस वर्ष पूर्व यानि वर्ष 1991 मे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक हरिश्चन्द्र व पुलिस क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण चतुर्वेदी व थानाध्यक्ष श्रीधर पाठक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।लेकिन इसके देखरेख के अभाव व बरसात में इसके अन्दर पानी भरने से ये अति जर्जर होती चली गई।

इसमें एक चौकी इंचार्ज का आवास व एक मुख्य आरक्षी निवास के अतिरिक्त आरक्षी बैरग बनी हुई है जो अति जर्जर हालात में है उसमें बरसात के दिनों में बारिश के चलते पुलिस कर्मी इधर उधर बैठ कर फरियाद सुनते हैं।

अब लोगो का मानना है कि देश के पहरेदार जो कि एक अस्तबल व घुड़साल का रूप धारण कर चुकी चौकी में रह रहे है यह किसी दुर्भाग्यपूर्ण से कम नही है।

प्रवीर गौतम

थानाध्यक्ष नीमगांव ने बताया कि चौकी के जर्जर होने की जानकारी उन्हें है चौकी की जगह का कही दूसरी जगह का ऐलाटमेन्ट है,पैसा आने पर चौकी का निरीक्षण कराया जायेगा।

राजेंद्र त्रिवेदी पूर्व प्रधान

सिकंदाबाद खीरी।

लगभग दस बर्षो पूर्व हमारे कार्यकाल मे चौकी की जगह की पैमाइश दूसरे स्थान पर कराई गई थी,लेकिन अभी तक पुलिस चौकी का निर्माण नही हुआ है।

कैंची धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त:एक युवक की मौत,

लखीमपुर–खीरी।बलरामपुर से उत्तराखंड स्थित कैंची धाम में नीम करोली बाबा के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार लखीमपुर गोकर्णनाथ के बीच सोमवार देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कार में सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतक की पहचान 25 वर्षीय अंकित जायसवाल निवासी महराजगंज तराई के रूप में हुई है। दुर्घटना में घायल हुए युवकों में सतीश कौशल, अरविंद सोनी, विनय जायसवाल और सुनील सोनी शामिल हैं। सभी घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।मृतक के भाई मुन्ना जायसवाल ने बताया कि अंकित अपने चार दोस्तों के साथ 11 जनवरी को बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए कैंची धाम गए थे। सोमवार को दर्शन कर सभी लोग कार से वापस घर लौट रहे थे।उन्होंने बताया कि सोमवार रात करीब 11रू30 बजे लखीमपुरदृगोला गोकर्णनाथ मार्ग पर उनकी कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भीषण था कि अंकित जायसवाल की मौके पर ही मौत हो गई।घटना की सूचना मिलते ही परिजन लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

पुलिस को फोन करने के बाद युवक ने जहर खाकर दी जान

लखीमपुर खीरी ।भीरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने दबंग और उसकी गर्लफ्रेंड से परेशान होकर मंगलवार को जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक ने इससे पहले डायल 112 पर फोन कर आत्महत्या की धमकी दी थी। उसकी हालत बिगड़ने पर उसे पहले बिजुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में लखनऊ ले जाते समय मौत हो गई।पुलिस के अनुसार, युवक ने डायल 112 पर कॉल कर आत्महत्या करने की बात कही थी। सूचना मिलने पर भीरा थानाध्यक्ष रोहित दुबे ने युवक से फोन पर बात कर उसे समझाने का प्रयास किया और थाने आने को कहा। हालांकि, युवक थाने आने को तैयार नहीं हुआ।इसी दौरान, डायल 112 की टीम युवक को खोजते हुए थाने ला रही थी। थाने के गेट पर पहुंचते ही युवक ने बताया कि उसने जहर खा लिया है। युवक को तुरंत बिजुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इलाज के दौरान भीरा पुलिस और युवक के परिजनों के बीच बहस होने की भी खबर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने एक वीडियो में युवक यह कहते हुए सुना जा रहा है कि उसने थाने में जहर खाया था।थानाध्यक्ष रोहित दुबे ने बताया कि यह मामला प्रेम प्रसंग से संबंधित है। युवक को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था, लेकिन वह लगातार फोन पर आत्महत्या की धमकी दे रहा था। मंगलवार को जब वह थाने पहुंचा, तो उसकी हालत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उसे तुरंत उपचार के लिए एक निजी वाहन से अस्पताल भेजा गया था।

जडौरा मे आयुष आपके द्वार के तहत नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन।

गोला गोकर्णनाथ खीरी।

दिनांक 13.01.2026 को गांव जड़ौरा में आयुष आपके द्वार के तहत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।

इस दौरान वहां तैनात आयुर्वेद डाक्टर हरि शंकर वर्मा व फार्मासिस्ट अनंग पाल सिह ने बताया कि कुछ दिन पहले आग से दुखी रोहन लाल वर्मा को परिवार को औषधीय भी दी गई। वही कैप के दौरान कुल 56 मरीज देखें गये व उनका संपूर्ण स्वस्थ परिक्षण भी किया गया। शिविर में सभी गांव वासियों का पूर्ण सहयोग रहा। इसके साथ ही बुखार, खांसी, दमा, अस्थमा, व जोड़ रोग आदि मरीजो को बदलते मौसम से अपने को बचाये रहने की जानकारी भी दी गई।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, ४० वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी २/३७६ रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ० प्र० से प्रकाशित।

सम्पादक
आरती पाण्डेय
eks-
9807059191- 9026560178
Email-
adbhutsamachar@gmail.com
adbhutsamachar@hotmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।